fo"k; lwph

**छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस**
छत्तीसगढ़ देश में अव्वल........ 15
भोजन का अधिकार................ 16
नवां अंजोर............................ 20

**मध्य प्रदेश स्थापना दिवस**
अमृत मंथन............................ 22
औद्योगीकरण की गति तेज.... 24

**लेख**
झारखण्ड में नक्सली तांडव... 10
गरीब बनाम असमानता......... 12
सुधार है या शिक्षा से मजाक. 14
आव्रजन भय से मुक्ति............. 29

**अन्य**
स्पेक्ट्रम घोटाला....................... 7
साक्षात्कार : सुशील मोदी....... 26

**प्रदेशों से**
झारखण्ड............................ 9
दिल्ली................................ 27
उत्तर प्रदेश........................ 28

**सम्पादक**
çHkkr >k] lkln
**सम्पादक मंडल**
lR;iky
d- d- 'kekZ
lathoz dqekj flUgk
**पृष्ठ संयोजन**
/keZUæ dkS'ky
**सम्पर्क**
Mk- eqdthZ Lefr U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl ¼ +91¼11½&23387887
InL;rk gsrq ¼ +91¼11½&23005700
**सदस्यता शुल्क**
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-
***e-mail address***
**kamalsandesh@yahoo.co.in**

**प्रकाशक एवं मुद्रक :** डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

lEikndh;



*सुन्दर जीवन निर्माण की आधारशिला भावशुद्धि है। भावशुद्धि के बिना कर्मशुद्धि असम्भव है।*

**-श्रीमद्भागवत गीता**

# युवराज का एजेंडा सिर्फ प्रोपेगेंडा

*fiछले कुछ महीनों से कांग्रेस के महामंत्री और कांग्रेसियों की भाषा में युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी सुर्खियों में हैं। समझ में नहीं आता कि वे देश के 90 करोड़ गरीब जनता का उपहास उड़ा रहे हैं या राजनीति में सादगी की पहल कर रहे हैं। किसी चीज की पहल एक दिवसीय नहीं होती। राजनीतिक स्टंट को पहल नहीं कहते, वह राजनीतिक स्टंट कहलाती है।*

*वे चापाकल पर नहाये और खबरों ने आश्चर्य व्यक्त किया। चापाकल पर भारत के लाखों लोग रोज नहाते हैं, लाखों चापाकल बंद है, वह खबर नहीं बनती पर युवराज जब चापाकल पर नहाते हैं तो मीडिया उसे सुर्खियों में ले आती है। हजारों लोग अब तक आंध्र भवन में भोजन कर चुके होंगे पर वह खबर नहीं है, खबर उस दिन बनती है जिस दिन आंध्र भवन में युवराज खाना खाते हैं। यह आंध्र प्रदेश के नागरिकों का अपमान है या सम्मान यह तो युवराज जानें लेकिन आम धारणा यह है कि यह पूरी तौर पर प्रोपेगेंडा है।*

*युवराज साइकिल पर चले, खबर बन गयी। लाखों लोग साइकिल पर चलते हैं, गिरते हैं और मरते हैं। साइकिल गरीबी का परिचायक है। किसी अमीर को उसका उपहास उड़ाने का हक नहीं है। राम जाने, कांग्रेस के युवराज ने गरीबों के दुपहिये पर बैठकर देश के करोड़ों गरीबों का उपहास उड़ाया है या फिर उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। युवराज तो आधे घंटे साइकिल पर चढ़कर 24 घंटे चैनल में चल गये, पर वर्षों से जो लोग साइकिल पर चल रहे हैं उनकी सुध वर्षों से सत्ता में रही कांग्रेस नहीं ले पा रही है।*

*भारत में रोज 14 करोड़ से अधिक लोग रेल से सवारी करते हैं पर उनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के युवराज पूरे तामझाम के साथ जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो वह खबरों में आ जाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि ट्रेन गरीबों की सवारी है। गरीब हमेशा रेल में ही चलते हैं पर उन गरीबों का रेल में चलना कभी खबर वालों की नजर में नहीं आता, सिर्फ राहुल गांधी के चार घंटे के सफर को वे अपने 24 घंटों की खबर का सफर जरूर बना लेते हैं।*

*कांग्रेस के युवराज गरीबों के घर गांव में रात में सोये। उनका एक रात सोना महत्वपूर्ण हो गया पर वर्षों से धरती को ही बिस्तर मानकर गांव में सोने वाले करोड़ों लोग खबरों की दुनिया से बाहर हैं क्योंकि गरीबों में कोई युवराज नहीं है, युवराज तो सिर्फ कांग्रेस*

में है। हमें पता नहीं कांग्रेस के युवराज ने गांव में सो कर गांव की जिंदगी का मजाक उड़ाया या उनकी जिंदगी को गले लगाया।

कांग्रेस के युवराज जेएनयू में विद्यार्थियों से मिले। जेएनयू में अनेकों लोग पूर्व में भी गये हैं पर वे कभी खबर नहीं बने। लाखों विद्यार्थी पढ़कर वहां से निकल चुके वे कभी खबर नहीं बनाये गए पर उनका जाना खबरों में आ गया। खबरों में आने के लिए कांग्रेस के युवराज अभी बहुत कुछ करेंगे और खबरों की दुनिया के लोग उनकी खबरों को जोरों से चलाएंगे।

मुझे समझ में नहीं आता अगर वह चापाकल में पूर्व में नहीं नहाये तो किसकी गलती थी, उनके परिवार की या भारत की? अगर वे रेल में पूर्व में नहीं चढ़े तो किसकी गलती थी, उनकी या रेल की? अगर वे गांव में कभी नहीं सोये तो गलती किसकी थी, उनकी या गांव वालों की? अगर वे कभी जेएनयू में नहीं पढ़े तो गलती किसकी थी, उनकी या जेएनयू की? अगर वे आंध्र भवन में पूर्व में नहीं गए तो दोष किसका है?

कांग्रेस के युवराज भारत की मानसिकता जानते हैं। भारत में रात–दिन अन्याय करने वाले नागरिकों को त्रस्त करने वाले कुख्यात से कुख्यात व्यक्ति की भी जब मृत्यु होती है तो लोग उसे जलाते हैं और सब कहते हैं ''राम–राम सत्य है और यह भी कहते हैं कि भगवान इन्हें स्वर्ग दे। हमारे भारत में अपने से बड़े न केवल उम्र में बल्कि ओहदे में चाहे छोटा भी क्यों न हो, उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि जिस भारत में सबका सम्मान होता है उस भारत में किसी राजनीतिज्ञ द्वारा इस तरह गरीबों का या गरीबों के जीने के तरीकों का उपहास उड़ाया जाता हो। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के युवराज के द्वारा किए जा रहे इन कृत्यों के पीछे कोई सादगी या एक नये प्रकार की जीवन शैली की शुरूआत की मानसिकता नहीं है। वे जानते हैं कि भारतीय मंजूषा, भारत का जनमानस ऐसे एक दिवसीय स्टंट को दिल खोलकर सराहते हैं और भारत के ऐसे जन–मन के साथ इस तरह का व्यवहार करना निश्चित तौर पर दुःखदायी है।

शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ कहने का अधिकार सिर्फ उसे है जो कहने से पहले उस तरह की जिंदगी जीता है। भला कौन मना करेगा यदि कांग्रेस के युवराज गांव में रहेंगे, पर वह एकदिवसीय प्रोपेगेंडा के लिए क्यों रहते हैं। वे क्यों नहीं बनाते किसी गांव में कुटिया जहां वे कुछ वर्ष रह सकें। वे आधे घंटे चापाकल पर क्यों नहाते हैं, वे क्यों नहीं चापकल पर रोज नहाते हैं। वे क्यों नहीं रोज आंध्र भवन में भोजन करते हैं, वे क्यों नहीं रोज गांवों में रात को सोते हैं। वे क्यों नहीं रोज रेल में चलते हैं। परंतु वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे तो ऐसी जिंदगियों से सदैव दूर रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे।

उनके द्वारा जो पहल की जा रही है उसकी नीयत ठीक नहीं है। यदि कार्य की प्रकृति की नीयत ठीक न हो तो उनके परिणाम अच्छे नहीं आते। मुझे याद है कांग्रेस के युवराज के पिता भी जब पहली बार गांव के दौरे पर गए और जब एक कुएं का अवलोकन किया तो कहा इसमें पानी कहां से आता है और यह भी कहा कि चावल कौन–से खेत में होता है। मुझे पता नहीं ये बातें झूठ थीं या सच, पर मुझे यह जरूर पता है कि वे कभी गांव में नहीं रहे तथा उनके द्वारा ऐसा पूछा जाना कोई अजूबा नहीं था।

आज कांग्रेस के युवराज द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उनके पीछे सिवाय प्रोपेगेंडा के और कोई एजेंडा नहीं है। न कोई नयी पहल है, न कोई परिणामकारी कदम है। हां, यह जरूर है कि भारतीय जनमानस में यह जताने की कोशिश की जा रही है कि गरीबों द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह तब तक खबर नहीं होती जब तक कोई अमीर उसकी नकल नही करता।

दुर्भाग्य यह है कि खबरों के बाजार में आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष की कोई अहमियत नहीं रह गयी है। अहमियत रह गयी है सिर्फ एक युवराज द्वारा किए जा रहे राजनीतिक हथकंडों की। गरीब या अमीर होना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन किसी अमीर को या किसी कांग्रेस के युवराज को गरीबों का अथवा गरीबों की जिंदगी का उपहास उड़ाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है।

मेरा तो देश के खबरचियों से भी आग्रह है कि आप उसे खबर नहीं बनायें, जो गरीबों का मजाक उड़ाते हों। आप उसे खबर नहीं बनायें, जो गांव का मजाक उड़ाते हों। आप उसे खबर नहीं बनाएं, जो सामान्य जन का उपहास उड़ाते हों क्योंकि जो लोग विलासिता की जिंदगी जीते हैं उनके लिए गरीब सिर्फ मतदाता है और ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे गरीबों को मूर्ख बनाते हुए उनके मत को कबाड़ने की नीयत मात्र है, जो सर्वदा गलत है। बिल्कुल गलत है।■

# भाजपा का चीन को भारत से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का परामर्श

Xत 16 अक्टूबर को चीन के राजदूत श्री झांग–यान ने भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर भेंट की। भेंट एक घंटे की रही।

श्री झांग ने दीपावली की शुभकामनाओं के साथ यह कहा कि वह हाल के घटनाक्रम पर कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं और उनकी सरकार दोनों देशों की जनता के मध्य विश्वास बनाना चाहती है। इस हेतु भाजपा जैसी प्रमुख पार्टी और भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भूमिका निभा सकते हैं।

*चीनी राजदूत झांग–यान की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात*

परस्पर विश्वास बढ़ाने के इस प्रयास में आगामी 16–20 नवंबर को चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के पोलितब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य श्री झाऊ–यांग कांग भारत आ रहे हैं। 2006 में राष्ट्रपति हू–जिंताऊ के भारत दौरे के बाद यह किसी चीनी नेता का सबसे प्रमुख भारत दौरा होगा। उन्होंने कहा कि श्री यांग श्री राजनाथ सिंह से भी भे मिलेंगे। फिर उन्होंने भारत–चीन संबंधों के वर्तमान वातावरण पर कुछ विचार व्यक्त किये जिसके प्रत्युतर में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की जनता और राजनैतिक दल के रूप में भाजपा चीन सहित सभी पड़ोसी देशों से सौहार्दपूर्ण संबंधों की पक्षधर है। भारत हमेशा एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। परन्तु यही बात दूसरी तरफ से भी अपेक्षित है। श्री सिंह ने स्मरण दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सन् 1962 की लड़ाई के बाद चीन की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे और अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 2003 की चीन यात्रा में उन्होंने भारत–चीन संबंधों में कई मील के पत्थर स्थापित किये। चीनी राजदूत ने इसे स्वीकार किया।

श्री सिंह ने कहा कि हाल की कुछ घटनाओं ने भारत–चीन संबंधों के विश्वास को क्षति पहुंचाई है। चीन द्वारा अरूणाचल प्रदेश पर बार–बार किया जा रहा दावा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि भाजपा भारतीय नेताओं की अरूणाचल यात्रा और विशेषकर हाल ही में प्रधानमंत्री की अरूणाचल यात्रा पर चीन द्वारा उठाई गयी आपत्ति को भाजपा पूरी तरह से अस्वीकार करती है।

श्री राजनाथ सिंह ने इसके अतिरिक्त कई अन्य मुद्दे भी उठाये, जिसमें चीनी दूतावास द्वारा कश्मीरियों को उपयुक्त वीज़ा न देना, एशिया विकास बैंक ने अरूणाचल प्रदेश की परियोजना के लिए सहायता रोकने का प्रयास किया जाना, पाक अधिकृत कश्मीर में चीन द्वारा अनेक गतिविधियों और परियोजनाओं को सहयोग तथा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का प्रयास आदि प्रमुख थे। उन्होंने चीनी सेना द्वारा बार–बार भारतीय सीमा में घुसपैठ और हाल की लद्दाख की घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया।

श्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भाजपा इन मुद्दों को चीन की सरकार के समक्ष रखने में भारत सरकार द्वारा किये जा रहे कूटनीतिक प्रयासों को पूरा समर्थन देगी। इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में कोई मतभेद नहीं है।

श्री सिंह ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी के वर्तमान दौर में आवश्यकता है कि भारत और चीन विकास आधारित आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रित हों न कि एक दूसरे के विरूद्ध अपनी उर्जा बरबाद करें। आज दोनों पड़ोसियों के मध्य विश्वास में कमी आई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण वातावरण को पुनर्स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि चीन ऐसे संकेत देना बंद करे जिनसे भारतीय जनमानस में अविश्वास और आशंका उत्पन्न होती है।

चीनी राजदूत ने कहा कि उन्होंने श्री राजनाथ सिंह द्वारा उठाये गये मुद्दों का संज्ञान लिया है। चीन की सरकार भारत के साथ बेहतर संबंध चाहती है परन्तु दोनों देशों के बीच कुछ अनसुलझे ऐतिहासिक मुद्दे हैं।

ये मुद्दे अत्यंत संवेदनशील हैं और इनकी संवेदनशीलता कभी–कभी मीडिया में इन मुद्दों की प्रमुखता के कारण बहुत बढ़ जाती है। अतः आवश्यक है कि भाजपा और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य में उच्च स्तर का संपर्क बना रहे ताकि संशय का उचित निराकरण हो सके। इस मुलाकात में चीनी दूतावास के काउंसलर श्री जी–पिंग तथा द्वितीय सचिव श्री ली–या तथा भाजपा विदेश प्रकोष्ठ के संयोजक तथा पूर्व राजदूत श्री एस.के. अरोड़ा एवं भाजपा अध्यक्ष के राजनैतिक सलाहकार डा0 सुधांशु त्रिवेदी उपस्थित थे। ■

# प्रधानमंत्री चीन पर सर्वदलीय बैठक बुलाएं

Çधानमंत्री जी के अरूणाचल प्रदेश के दौरे के प्रति विरोध व्यक्त करने वाली चीन की कल की सरकारी टिप्पणी ने अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति के सभी मानकों को तार–तार कर डाला है। विरोध के लिए प्रयुक्त भाषा न केवल कड़ी निंदा किए जाने योग्य है बल्कि, भारत तथा इसके सामरिक हित के विरूद्ध युद्धकारिता की मनोवृत्ति की परिचायक भी है। मगर भारतीय जनता पार्टी को भारत के विदेश मंत्री के प्रत्युत्तर की भाषा की क्षमायाचनात्मक ध्वनि तथा भावना को लेकर गहरी निराशा हुई है, जिससे देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के प्रति सरकार की इच्छाशक्ति तथा क्षमता के बारे में लोगों के मन में गंभीर सन्देह पैदा हो गया है।

लगभग विगत दो वर्षों से चीन भारत के विरूद्ध बढ़–चढ़कर शत्रुता भाव प्रदर्शित कर रहा है और न केवल वहां के राजदूत द्वारा बल्कि, वहां का उच्चतम राजनीतिक नेतृत्व भी अरूणाचल प्रदेश पर बार–बार अपना दावा कर रहा है। ऐसा प्रयास बहु–पक्षीय मंचों पर भी हो रहा है। भारत सरकार का उत्तर बेहद घिसा–पिटा होता है। वर्ष 1962 की दुर्भाग्यपूर्ण अवधि के दौरान तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व भी अक्षाई चिन के बारे में ऐसी ही घिसी–पिटी टिप्पणी किया करता था। देश अब उस भू–क्षेत्र को प्रायः भूल बैठा है, जिसका आकार लगभग स्विट्जरलैंड के आकार के बराबर है। अब पूरा अरूणाचल प्रदेश चीन के रेडार के नीचे आ गया है, जिसका आकार ताइवान के आकार का तीन गुना है। इतिहास पुनः अपने आपको पर चिंता होनी ही चाहिए में दोहरा रहा है, जिस चीन की आक्रामक हरकतों का न केवल कायरतापूर्ण उत्तर दिया जा रहा है बल्कि, उसको कम करके भी पेश किया जा रहा है। चीन, हिमालय क्षेत्र पर सभी ओर से अतिलंघन करके दबाव बढ़ा रहा है, परंतु भारत सरकार ने उसके बारे में सभी सूचनाओं पर अंकुश लगा दिया है। कुछ भूली–भटकी सरकारी टिप्पणियां संकेत देती हैं कि गत वर्ष के उल्लंघनों की संख्या की तुलना में इस वर्ष कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है किंतु, उल्लंघनों की सही संख्या का खुलासा नहीं किया जा रहा है। स्मरणीय है कि वर्ष 2007 में उल्लंघनों की संख्या 104 थी, जो वर्ष 2008 में बढ़कर 270 हो गई थी। इस बार के उल्लंघनों की संख्या में वृद्धि उल्लेखनीय है या नहीं इसका पता तभी चलेगा, जब इसकी संख्या की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। भाजपा मांग करती है कि चीन के द्वारा किए गए सीमा–अतिलंघनों की संख्या का शीघ्र खुलासा किया जाए।

***भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा संसद सदस्य श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 14 अक्टूबर को जारी प्रेस वक्तव्य***

मगर निर्णायक मुद्दा यह उठता है कि हमारी सरकार के झुकते जाने तथा सीमा–अतिलंघनों को जानबूझकर कम बताए जाने के बावजूद चीन दबाव बढ़ा रहा है। इतिहास बड़े भयावह रूप से अपने आपको दोहरा रहा है। चीन की युद्ध जैसी हरकतें उसी के अनुरूप लगती हैं जैसी कि 1962 में की गई थीं। उस समय के दौरान स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने किसी के साथ सलाह–मशविरा नहीं किया था और वह एक छोटे से करीबी समूह के द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर रही थी, जिसके परिणाम देश के लिए विनाशकारी बने। हम देखते हैं कि वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। चीन के आक्रामक मनसूबों के विरूद्ध कड़ा जवाब देने के लिए व्यापक सलाह–मशविरा और राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी चीन के साथ अच्छे संबंध चाहती है लेकिन, ये संबंध हमारी क्षेत्रीय अखंडता की कीमत पर स्थापित नहीं होने चाहिए। चीन के साथ संबंध चुनिंदा सिविल–सेवकों की और हमारे विद्वान विदेश मंत्री, जिन्हें अभी अपनी छाप छोड़नी है, की सलाह पर निर्धारित नहीं होने चाहिए।

इस घटनाक्रम का पुनर्आकलन किया जाना और इसके बारे में प्रभावी प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। भाजपा तद्नुसार मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी चीन के सम्पूर्ण मंसूबों, उसके साथ हमारे संबंधों और चीन को किस प्रकार का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, के बारे में व्यापक सलाह–मशविरा करने और आम सहमति बनाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। ■

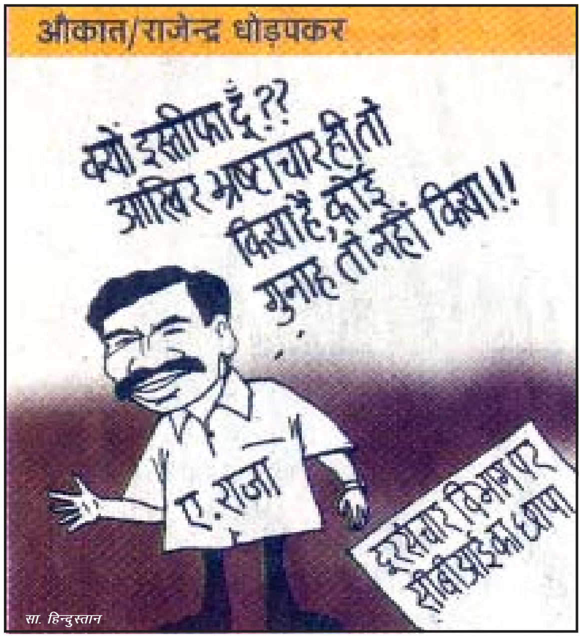

# घोटाले का संचार

दूरसंचार मंत्रालय के कार्यालयों में केंद्रीय जांच ब्यूरो की छापेमारी मात्र से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में वास्तव में घोटाला किया गया। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह तो पहले ही सामने आ चुका है कि दो नई कंपनियों ने स्पेक्ट्रम आवंटन के चंद दिनों बाद ही अपनी हिस्सेदारी बेचकर करोड़ों रुपये बटोर लिए थे। इसी तरह यह आरोप भी बहुत पहले सतह पर आ गया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता के चलते सरकार को 22 हजार करोड़ रुपये की चपत लगी इस आरोप के साथ करीब सौ सांसदों ने प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र तो भेजे ही, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश भी की। यह आश्चर्यजनक है कि घोटाला होने के परिस्थितिजन्य प्रमाण सामने होने के बावजूद सीबीआई को सक्रियता दिखाने में एक वर्ष से अधिक का समय क्यों लग गया? कहीं इसलिए तो नहीं कि दूरसंचार मंत्रालय द्रमुक नेता ए. राजा के पास है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्रीय सत्ता अपने इस सहयोगी दल को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर देश को बताया जाना चाहिए कि सीबीआई के अधिकारियों को अपने दफ्तर से चंद कदम की दूरी पर स्थित संचार भवन पहुंचने में इतना समय क्यों लगा। यह संभवतः पहली बार है जब सीबीआई ने किसी मंत्रालय के मुख्यालय पर छापा मारा हो। इस छापे के बावजूद दूरसंचार मंत्री ए. राजा का यह कहना राजनीतिक दुस्साहस के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कि मेरे त्यागपत्र का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि उन्हें त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं महसूस हो रही तो फिर किसका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, यह सामान्य बात नहीं कि किसी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के यहां छापे पड़ें और संबंधित मंत्री जी यह फरमाएं कि इससे उन्हें कोई लेना–देना नहीं।

यह घोर निराशाजनक है कि जिस गड़बड़ घोटाले में अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी उसमें छानबीन की शुरुआत हो रही है। आखिर यह क्यों न मान लिया जाए कि जब उच्च पदों पर बैठे लोग कोई बड़ा कारनामा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच बरता जाता है, क्या यह उम्मीद की जाए कि राजा को मंत्री पद छोड़ने की सलाह देने में संकोच का परिचय नहीं दिया जाएगा। ऐसे आसार कम ही हैं, क्योंकि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बार राजा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने से हिचक रहे थे। कहीं इस हिचकिचाहट का कारण स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता ही तो नहीं थी। वस्तुस्थिति जो भी हो, यदि राजा अपने पद पर बने रहते हैं तो केंद्र सरकार के लिए अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना कठिन होगा। यही नहीं, इस स्थिति में इस पर भी यकीन करना मुश्किल होगा कि सीबीआई इस घोटाले की तह तक पहुंच सकेगी। यह शुभ संकेत नहीं कि जहां विपक्षी दल राजा के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं वहीं कांग्रेस उनका बचाव करती दिख रही है। ऐसा करना उसकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इससे उसे बदनामी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार चलाने की मजबूरी के नाम पर राजनीतिक अनैतिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजा के मामले में कांग्रेस का रवैया घपले–घोटाले के सिलसिले को कायम रखने वाला है।■

*स. दैनिक जागरण*

# घोटाले में लिप्त संचार मंत्री को बर्खास्त करे सरकार : भाजपा

स्पेक्ट्रम प्रकरण में अनियमितताओं को देखते हुए सीबीआई ने मंत्री के कार्यालय पर छापा मारा। संचार मंत्रालय ने सपेक्ट्रम का वितरण कुछ ऐसी कंपनियों को किया, जिनके निकट संबंध संचार मंत्री ए. राजा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने बजट सत्र में स्पेक्ट्रम वितरण में अनियमितताओं का मुद्दा गंभीरता के साथ उठाया था और प्रधानमंत्री से मांग की थी कि स्पेक्ट्रम वितरण की जांच की जाए, क्योंकि यह कई हजार करोड़ का घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी स्पेक्ट्रम घोटाले में लिप्त संचार मंत्री श्री ए. राजा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करती है।

प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर ए. राजा को बर्खास्त करें, ताकि निष्पक्ष रूप से सीबीआई स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर सके। एक सवाल के जवाब में श्री प्रसाद ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इस घोटाले की जानकारी थी जैसा कि ए. राजा ने कहा है तो हम मांग करते है कि प्रधानमंत्री स्थिति को स्पष्ट करें, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार इतने हजार करोड़ के घोटाले में कार्रवाई इतनी देरी से क्यों की गई ? और हम मांग करते है कि सीबीआई निष्पक्ष रूप से इस घोटाले की जांच करे और दोषी लोगों को सजा मिल सके। हम आशंका व्यक्त करते है कि अगर वर्तमान संचार मंत्री के रहते स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच सीबीआई करती रहेगी तो संचार मंत्री उस कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास करते रहेगें और सीबीआई दोषियों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हम मांग करते है कि प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर संचार मंत्री श्री ए. राजा को अविलंब बर्खास्त करें।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के मुख्य प्रशासक का एक भूमि घोटाले में शामिल होने का मामला सामने आया है और उस भूमि घोटाले में केन्द्र के दो मंत्रियों का नाम भी उजागर हुआ है। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं गंभीरता के साथ समयबद्ध होकर इस घोटाले की जांच कराएं। ■

# क्या पर्यावरण मंत्री विकसित देशों के हितों की रक्षा कर रहे हैं?

Vk इम्स आफ इण्डिया की एक रिपोर्ट से पता चला है कि पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हुए 'जलवायु परिवर्तन' लाने की बात का सुझाव दिया है। इस रिपोर्ट में कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है कि भारत को क्योटो प्रोटोकाल तोड़ देना चाहिए, उसे विकासशील देशों के समूह–जी–7 से अपने को अलग कर लेना चाहिए और ग्रीन हाउस उत्सर्जन वचनबद्धता को अपनाना चाहिए। श्री रमेश का यह भी सुझाव है कि भारत को अपने खर्च पर ऐसे उपायों की बाहय जांच करनी चाहिए।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली द्वारा 19 अक्टूबर को जारी प्रेस वक्तव्य

भारतीय जनता पार्टी जलवायु परिवर्तन सम्बंधी भारत की इस बातचीत की स्थिति में बदलाव और परिवर्तन लाने के प्रयास पर गहरा खेद प्रगट करती है। निष्पक्ष सिद्धांत तो यही है, जिसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया है कि ''प्रदूषण फैलाने वाले देशों को ही दण्ड भुगतना पड़ता है''। भारत तो ग्रीन हाउस गैस के मामले में प्रति व्यक्ति केवल 1.2 टन का उत्सर्जन करता है जबकि अमरीका इसके मुकाबले 20 टन का उत्सर्जन करता है। यह तो विकसित राष्ट्र हैं जिन्होंने क्योटो प्रोटोकाल के दायित्वों का निर्वाह नहीं किया है, जिसके बारे में भारत इसका परित्याग करने का सुझाव दे रहा है। इस प्रकार विकसित देशों की स्थिति को स्वीकार करके भारत ऐसी स्थिति स्वीकार करने की तैयारी कर रहा है जिससे चार बड़े विकासशील देशों, अर्थात् भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा उठाए गए कदम समाप्त होकर रह जाएंगे और जिससे भारत आधारस्तर से नीचे की उत्सर्जन मात्रा की स्थिति में पहुंच जाएगा। मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि भारत घरेलू कानूनों से बंधा है और अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने के लिए खुला है।

भारत की इस परिवर्तन की स्थिति से विकासशील देशों की एकता पूरी तरह से भंग हो जाएगी जिसमें 131 राष्ट्रों का एक बहुत बड़ा समूह शामिल है और जो जी–77 देशों के नाम से विख्यात है। इससे विकासशील देशों के नेतृत्व के रूप में भारत की विश्वसनीयता को धक्का लगेगा और इसका प्रभाव इन दिनों चल रही डब्ल्यूटीओ में दोहा दौर की बातचीत पर भी पड़ेगा।

इस परिवर्तन की स्थिति का सीधा और अनिवार्य परिणाम यह होगा कि भारत ऐसी वचनबद्धता स्वीकार करेगा जिससे विकसित देशों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण की कीमत भारत चुकाएगा। हमारी उर्जा कीमत कई गुणा बढ़ जाएगी जिससे हमारे औद्योगिक विकास की प्रगति रूक कर रह जाएगी और हमारा निर्धनता उन्मूलता का कार्यक्रम धीमा पड़ जाएगा। हमारी जनसंख्या के कमजोर वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता भी बुरी तरह से प्रभावित होगी।

क्या पर्यावरण मंत्री अपनी निजी व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत कर रहे हैं या वह एक बहुत बड़ी लॉबी की ओर से यह अभियान चला रहे हैं? यदि ये उनके अपने निजी व्यक्ति विचार है तो क्या वह जलवायु परिवर्तन सम्बंधी मामले में भारत के प्रमुख वार्ताकार बने रह सकते हैं? परन्तु यदि वह उस बड़ी लॉबी के प्रवक्ता और ''ट्रायल बेलून' का काम कर रहे हैं तो इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार होना चाहिए। क्या यह यूपीए सरकार का युनाइटेड स्टेट्स और अन्य विकसित देशों के लिए 'गरीब भारत' की कीमत पर दिवाली उपहार है?

इससे पूर्व, बैंकाक में चल रही बातचीत के समय भी वह एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र 'मिंट' में टिप्पणी करके भारत वार्ता को गहरा धक्का पहुंचा चुके हैं। एक तरफ जहां हमारे वार्ताकार विपरीत स्थिति अपना रहे थे, वहीं अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल ने इसके समर्थन में हमारे मंत्री महोदय के बयान को उद्धृत करके हमारे वार्ताकारों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसी प्रकार, क्योटो प्रोटोकाल पर एडब्ल्यूजी के चेयरमैन ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल से पूछ लिया था कि क्या भारत ने अपनी परम्परागत स्थिति को बदल लिया है और प्रतिनिधिमण्डल से उस समाचार पत्र की प्रति देकर कहा था कि वह भारत सरकार के मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दे। ऐसी विध्वंसकारी गतिविधियों से आखिर वह किसके हितों का संरक्षण कर रहे हैं? ■

# झारखंड में विधानसभा चुनाव पांच चरणों में

चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य में चुनाव 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक पांच चरणों में होंगे। 23 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने 23 अक्टूबर को नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में पांच चरणों के तहत 27 नवंबर, दो दिसंबर, आठ दिसंबर, 12 दिसंबर और 18 दिसंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि इस साल जनवरी से झारखंड में राष्ट्रपति शासन होने के कारण राजनीतिक असमंजस का माहौल बना हुआ था। हालांकि राज्य में सितंबर 2006 से ही राजनीतिक

अस्थिरता बनी हुई थी। निर्दलियों ने अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा दी थी। उस वक्त कांग्रेस, राजद या झामुमो में से कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगस्त 2008 में कोड़ा को हटाकर शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। जनवरी 2009 में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हार जाने के बाद शिबू सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। तभी से झारखण्ड में केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू किया था।

| | |
|---|---|
| प्रथम चरण | 27 नवंबर |
| दूसरा चरण | 2 दिसंबर |
| तीसरा चरण | 8 दिसंबर |
| चौथा चरण | 12 दिसंबर |
| पांचवां चरण | 18 दिसंबर |
| मतगणना की तिथि | 23 दिसंबर |

■

# चीनी के दाम सर्वोच्च स्तर पर

त्योहारी मौसम खत्म होने के बावजूद चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। यह अपने सर्वोत्तम ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। 22 अक्टूबर को थोक बाजार में चीनी की कीमत 32.50 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गयी। डबल रिफाइंड चीनी के थोक भाव तो 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए। इसके साथ ही खुदरा बाजार में चीनी के दाम 36. 37 रुपये प्रति किलोग्राम हो चुके हैं।

बाजार में तेजी के रुख को देखते हुए कीमत में कोई कमी होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। बाजार में चीनी की आपूर्ति कम होने से उठाव में तेजी आ गयी है। कृषि मंत्री शरद पवार ने रिफाइंड चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अवधि नवंबर, 2009 से बढ़ाकर दिसंबर, 2010 तक करने की घोषणा की है। लेकिन इसका कोई असर चीनी बाजार पर नहीं पड़ा है।

सरकार 2009.10 के लिए 160 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगा रही है जबकि सालाना घरेलू खपत 230.240 लाख टन है। अगस्त माह के दौरान थोक बाजार में चीनी की कीमत 32 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गयी थी लेकिन सरकारी सख्ती के बाद चीनी के थोक भाव 28.29 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए थे।

कारोबारी बताते हैं कि चीनी के दाम में गत 15 अक्टूबर से ही तेजी शुरू हो गयी थी। उस दिन यह कीमत 31–31. 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो चुकी थी। 16 अक्टूबर से चीनी मिलें बंद हो गयी थीं और गत 20 अक्टूबर को मिलें खुलने के बाद भी चीनी में तेजी का रुख जारी है।

कारोबारियों ने बताया कि कीमत तेज होने से उठाव में भी तेजी आ गयी है। क्योंकि कीमतों में और तेजी की आशंका के मद्देनजर उठाव ज्यादा होने लगता है। इन दिनों दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुकाबले महाराष्ट्र से चीनी की आपूर्ति ज्यादा हो रही है। थोक कारोबारियों के मुताबिक हर सप्ताह दिल्ली में महाराष्ट्र से दो रैक चीनी की आपूर्ति की जा रही है।

एक रैक में 20.30 हजार बोरी (1 बोरी = 100 किलोग्राम) चीनी होती है। वे यह भी कह रहे हैं कि बाजार में चीनी की आपूर्ति की लाइन सुचारू तरीके से नहीं चल रही है। यहां तक कि आयातित रिफाइंड चीनी की आपूर्ति भी अभी बाजार में नहीं हो रही है। सरकार के मुताबिक अब तक 3 लाख टन से अधिक रिफाइंड चीनी का आयात हो चुका है।

अक्टूबर माह के लिए सरकार ने 20 लाख क्विंटल चीनी का कोटा जारी किया है जो कि एक माह के लिए पर्याप्त है। थोक व्यापारी चीनी मिल वालों से डिलीवरी लेते हैं। चीनी के दो प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई अभी शुरू नहीं हुई है। यहां नवंबर माह में गन्ने की पेराई शुरू होगी। ■

# झारखण्ड में नक्सली ताण्डव

**gfjvke x|rk**

Vभी गढ़चिरौली में नक्सली हिंसा में मारे गए 18 पुलिस कर्मियों का दर्द ताजा ही है, झारखण्ड भी दो दिन तक नक्सलियों के रहमोकरम का मोहताज रहा। इन दो दिनों में वे जहां भी चाहते थे आगजनी, हत्या, रेल पटरी उखाड़ने तथा रास्ता रोकने का आदेश देते और वही काम होता रहा। इस पूरे समय झारखण्ड की पुलिस और प्रशासन के ईमानदार अधिकारी दुबके रहे और राज्यपाल के मुंह पर कालिख पोतते रहे। राज्यपाल के. शंकर नारायणन ने हाल ही में इन कथित ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा था कि 'ईमानदार अधिकारियों को नक्सलवादी नहीं मारते।' इस टिप्पणी के बाद राज्य में राज्यपाल की जबरदस्त आलोचना हुई थी और यह राजनीतिक मुद्दा बन गया था। नक्सली हिंसा के विषय में की गयी यह टिप्पणी सर्वथा अनुपयुक्त थी और वास्तविकता से भी दूर थी। क्योंकि राज्य में नक्सली हिंसा के जो भी शिकार हुए हैं उनमें से अधिकांश या तो अपना काम ईमानदारी से करने वाले थे या नक्सलियों के लिए किसी न किसी रूप में खतरा बन चुके थे या फिर सामूहिक हिंसा में शिकार हुए निरपराध लोग, इनमें लोहरदगा के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह तथा बुंडु के पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद मिश्रा, जिनकी बहादुरी एक मिसाल बन गयी है, जैसे अधिकारी, बाबूलाल मरांडी का युवा पुत्र आदि शामिल हैं। दो दिन तक चली नक्सली हिंसा में केंद्र व राज्य सरकार के दावों की भी पोल खुल गयी। हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् ने दावा किया था कि नक्सली हिंसा को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा केंद्र राज्यों को सब तरह के साधन मुहैया कराएगा। ये सब दावे धरे रह गए। नक्सली हिंसा के इस माहौल में ही राहुल गांधी की यह टिप्पणी तो राज्यपाल के मुंह पर एक तमाचा ही है कि 'इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है।'

अपने कुछ वरिष्ठ साथियों की गिरतारी के विरोध में नक्सलवादियों ने दो दिन के बंद की अग्रिम सूचना दी थी। यह सरकार को एक चुनौती थी कि उन्होंने खुफिया विभाग के एक इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदुवार को बंधक बनकर सरकार से मांग की थी कि वे उनके साथियों को छोड़ें नहीं तो इंदुवर को मार दिया जाएगा।' सरकार की ओर से तीन दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और नक्सलियों ने फ्रांसिस का गला काटकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। वह भी राजधानी से महज 5–7 किलोमीटर की दूरी पर।

यह है राज्य का खुफिया तंत्र, जो सात दिन तक अपने एक ईमानदार इंस्पेक्टर, जिनकी सूचनाओं पर पुलिस को कई बड़ी सफलताएं मिलीं थीं, की रक्षा के लिए भी पुलिस महकमा अंधा–बहरा बना रहा। उनकी पत्नी ने बार–बार अनुरोध किया कि नक्सलवादियों से बात तो की जाए, परंतु राज्यपाल को लगता था कि नक्सली ईमानदार अधिकारियों को नहीं मारते। इस कारण उन्होंने किसी भी तरह का प्रयास नहीं कराया। इतना जरूर किया कि इंदुवर की हत्या के तुरंत बाद उनकी पत्नी को एक शिक्षिका की नौकरी तथा उनकी मौत की कीमत के रूप में मुआवजा भुगतान कर दिया। भाजपा ने भी अपनी तरफ से एक लाख रुपये की धनराशि इंदुवर की पत्नी को दी तथा उनकी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। ज्ञातव्य है कि इस पुलिस अधिकारी को उसके बार–बार प्रयास करने के बाद भी पिछले 5 माह से वेतन भी नहीं दिया गया था। मरणोपरांत यह राशि भी नहीं दी जाती, यदि पूरा पुलिस महकमा सरकार के विरोध में न खड़ा हो गया होता।

दो दिन के बंद में नक्सलियों ने क्या–क्या नुकसान पहुंचाया इसका अभी आकलन हो रहा है। इस बंद का शिकार दुमका के पैनम कोलमाइंस के दो अधिकारी हुए, जिनको नक्सलियों ने सुबह की सैर के समय रायफल की गोलियों से भून डाला। वहीं बोकारो के पास रेलवे लाइन को बम से उड़ा दिया। इन दो दिनों में दो लोग मारे गए, एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, कई मोबाइल टावर उड़ाए गए, पुलिस की शरणस्थली बने कई स्कूलों को तथा कई ऐसे पुल पुलियों को उड़ा दिया गया जहां से पुलिस उन तक पहुंच सकती थी। राज्य की राजधानी को जोड़ने वाले 19 बड़े राजमार्ग, जिनमें जी.टी.रोड, मुबई राजमार्ग, रांची–टाटा राजमार्ग, तथा गिरिडीह व धनबाद को रांची से जोड़ने वाली सड़कें हैं, दो दिन तक पूरी तरह वीरान रहीं। जो वाहन जहां थे वहीं रुके रहे। सवारियों को भी बंधक जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा। बरही से गुजरने का प्रयास कर रही एक तीर्थयात्री बस पर बम फेंक कर कई तीर्थयात्रियों को घायल कर दिया गया। रेल मार्गों को भी नक्सली हिंसा से गुजरना पड़ा। इस बीच हावड़ा–मुंबई रेलमार्ग को जाम करने का प्रयास किया गया। रेलों को जहां–तहां रोक दिया गया, उनको झारखण्ड में नहीं आने दिया गया। सरकार कहीं भी दिखायी नहीं पड़ी। इस पर भी जब भाजपा ने राज्यपाल के इस्तीफे की मांग की तो उन्होंने सपाट जबाव दिया कि वह काम कर रहे हैं तो इस्तीफा क्यों दें? काम क्या कर रहे हैं, यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने राज्य में स्थानांतरणों की चक्की चला रखी है। हर अधिकारी आशंका से भरा हुआ काम कर रहा है या कांग्रेस से जुड़े राजनीतिक दलालों से संपर्क कर रहा है। इन दो दिनों में लगभग 200 करोड़ रुपयों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। माओवादी (भाकपा) नाम का यह नक्सली संगठन आज राज्य में किसी दुश्मन देश की सेना की तरह काम कर रहा है। इस वर्ष अब तक रपट की गयी घटनाओं में 247 नक्सली घटनाएं हो चुकी हैं। इस वर्ष पुलिस ने 81 मुठभेडें की हैं जिनमें अधिक नुकसान पुलिस का ही हुआ है।■

# नक्सलवाद पर ठोस कार्रवाई की जाए

*भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद, श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा नक्सली हमलों पर जारी प्रेस विज्ञप्ति*

महाराष्ट्र में नक्सली हमले में सोलह सिपाहियों की दर्दनाक हत्या पर भारतीय जनता पार्टी शोक व्यक्त करती है। नक्सलवाद की कार्रवाई के दौरान पुनः इस तरह का हमला नक्सलवाद के प्रति केन्द्र सरकार के रूख पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। जो सोलह सिपाही नक्सली हमले में शहीद हुए है उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए गृहमंत्री पी चिदम्बरम से यह जानना चाहेगी कि आखिरकार उनके उस नीति का क्या हुआ जिसमें वे निरंतर ठोस कार्रवाई की बात करते हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने हाल मे दिल्ली में हुए पुलिस महानिदेशकों एवं मुख्यमंत्रियों की बैठक में नक्सलवाद की समस्या का पूर्ण निराकरण और नक्सल उन्मूलन की बात कही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नक्सलवादी देश के कोने–कोने में फैल कर मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे है एवं सरकारी तंत्र को बेखौफ खुली चुनौती दे रहे है।

परंतु कांग्रेस पार्टी ने हर ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को कहीं न कहीं राजनीतिक रंग दे कर विवादित करने का प्रयास किया है। कॉंग्रेस के श्री राहुल गॉंधी ने हाल के बयानों में एक प्रकार से नक्सली व नक्सलवाद का समर्थन करते हुए गरीबी और प्रशासनिक दुराव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और ऐसा ही बयान हाल–फिलहाल झारखंड के राज्यपाल ने भी दिया है। कॉंग्रेस आलाकमान द्वारा इस प्रकार के विरोधाभासी बयानों से सरकार के नक्सलवाद उन्मूलन नीतियों को संदेह के घेरे में डालता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से यह मॉंग करती है कि वह कॉंग्रेस की इस विरोधाभासी स्थिति को स्पष्ट करें।

हाल में पश्चिम बंगाल के लालगढ़ की घटनाओं में ऐसे संवाद मिले हैं जिसमें माओवादियों से कॉंग्रेस और तृणमूल कॉंग्रेस के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के संकेत मिलते हैं। प. बंगाल की घटनाओं में कहीं न कहीं कॉंग्रेस कार्यकर्ताओं की संलिप्तता और माओवादियों का बढ़ता प्रभाव एक बड़ी चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी आज नक्सलवाद के प्रति सरकार की मंशा पर सरकार का स्पष्टीकरण व अपनी शंका का निराकरण चाहती है। जिस प्रकार से आतंकवाद के मामले को कॉंग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता से जोड़कर राजनीति करने का प्रयास किया उसी प्रकार से कहीं पुनः वह नक्सलवाद को गरीबी से जोड़कर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास तो नहीं कर रही है? ये दोनों विषय देश के लिए खतरनाक हैं और कॉंग्रेस की मंशा को स्पष्ट करते है।

**एयर इण्डिया के पायलटों का कॉंग्रेसी मंत्रियों पर दुर्व्यवहार का आरोप**

एयर इण्डिया के पायलटों ने अपने प्रबंधन को यह लिख कर सूचित किया है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री व सांसद, इकोनॉमी क्लास की कम पैसे में टिकट लेकर उच्च श्रेणी के सीटों पर जबरन कब्जा करते हैं। जब सांसदों व मंत्रियों को ऐसा करने से मना किया जाता है तो ऐसा आरोप है कि वह पायलटों व परिचारिकाओं के साथ दुर्व्यवहार पर उतर आते है जिसके कारण एयर इण्डिया के हवाई जहाजों को उड़ान में विलम्ब होता है। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी की सादगी के नाम पर इकोनॉमी श्रेणी के टिकट लेने के बाद ये कौन ऐसे मंत्री है जों सादगी का ढ़ोंग रच उच्च श्रेणी में बैठने हेतु जहाज में जोर जबरदस्ती करते हैं।

जो अल्पव्यय का प्रचार एवं प्रसार कॉंग्रेस द्वारा किया गया है ऐसी घटनाओं से ढ़ोंग प्रतीत हो रहा है। हाल–फिलहाल में कॉंग्रेस नेताओं ने ऐसा प्रदर्शन किया जो अपने आप में चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी यह मॉंग करती है कि सादगी का प्रचार प्रसार में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की खिल्ली न उडाये व सादगी अपने आप में आचरण में होनी चाहिए न की दिखावे में जो कि आज कॉंग्रेस के मंत्रीयों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।■

## झरोखा

सा. दैनिक जागरण

# गरीबी बनाम असमानता

Mk- Hkjr >|u>|uokyk

tनहितकारी आर्थिक नीति के दो उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य गरीबी उन्मूलन का है और दूसरा समानता परक समाज के गठन का। दोनों उद्देश्यों में भिन्नता है। गरीबी उन्मूलन का अर्थ है कि हर नागरिक को जीविका के न्यूनतम साधन उपलब्ध हो जाएं। असमानता में वृद्धि के साथ–साथ यह उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बड़ी कंपनियों द्वारा अरबों रुपए के लाभ कमाए जाएं और उनके अधिकारी ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करें तो इससे असमानता बढ़ती है, लेकिन इन्हीं कंपनियों से कर वसूल करके गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध कराया जाएए तो इससे गरीबी दूर होगी। इस प्रकार गरीबी उन्मूलन एवं असमानता साथ–साथ चल सकते हैं। परंतु समानता से गरीबी उन्मूलन का होना जरूरी नहीं हैए जैसे कम्युनिस्ट देश अलबानिया एवं उत्तरी कोरिया समानता परक हैं, परंतु उन देशों में गरीबी व्याप्त है। इसके अलावा आदिवासी समाज में समानता एवं गरीबी साथ–साथ चलते हैं। यदि अमीरों का पैसा जब्त करके गरीबों मे बांट दिया जाए तो समानता स्थापित होगी, परंतु निवेश के अभाव में गरीबी दूर नहीं होगी। अतः हमें निर्णय करना होगा कि गरीबी उन्मूलन एवं समानता में हम किस उद्देश्य को ज्यादा महत्व देते हैं और तदानुसार आर्थिक नीतियां तय करनी होंगी।

मेरी समझ से असमानता में वृद्धि अनिवार्य है। जब ब्लैक होल से निकल कर सृष्टि का जन्म हुआ तो वह 'समान' रही होगी। समय क्रम में अलग–अलग तत्व प्रकट हुए और उन तत्वों में असमानता उत्पन्न हो गई। इसके बाद जीव व निर्जीव तथा चेतन व अचेतन का अंतर उत्पन्न हुआ। असमानता बढ़ती गई। यह भी देखा जाता है कि एक ही परिवार में एक बेटा बहुत आगे बढ़ जाता है जबकि दूसरा पीछे रह जाता है। कारण यह कि हर व्यक्ति की क्षमता और योग्यता बराबर नहीं होती, जैसे एक किसान टिशू कल्चर के पौधे लगाकर अच्छी रकम कमाता है और दूसरा ऐसा नहीं कर पाता। ज्ञान एवं श्रम के अंतर के कारण आर्थिक असमानता उत्पन्न हो ही जाती है। वर्तमान समय में असमानता में वृद्धि होने का एक और कारण यह है कि नई तकनीकों द्वारा उत्पादन में श्रम का न्यून उपयोग होता है। एक कुशल कर्मचारी 10.20 आटोमेटिक लूम का संचालन कर लेता है। ऐसे कर्मचारी का वेतन ऊंचा होना स्वाभाविक है। साथ–साथ आटोमेटिक लूम के उपयोग के कारण अकुशल श्रमिकों की माग कम हो जाती है और उनके वेतन कम हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास के प्रारंभिक समय में आम आदमी की खपत को घटा कर निवेश किया जाता है, जिससे असमानता बढ़ती है, जैसे अठारहवीं सदी के इंग्लैंड में श्रमिकों के वेतन न्यून से भी कम कर दिए गए और बची रकम को फैक्ट्रियों में निवेश किया गया। एक तरफ स्टीम इंजिन से चलने वाली कपड़ा मिलें लगाई जा रही थीं और दूसरी तरफ श्रमिक भूखों मर रहे थे। इन फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में उत्पादन हुआ और उद्यमी अमीर हो गए। श्रमिक के वेतन में कटौती और उद्यमी की आय में वृद्धि साथ–साथ हुई। भारत एवं चीन आज इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दोनों देशों में असमानता में भारी वृद्धि हो रही है और साथ–साथ आर्थिक विकास दर चरम पर है। भारत में नक्सलवादी गतिविधियों का बढ़ना एवं आर्थिक विकास दर का नौ प्रतिशत तक पहुंचना साथ–साथ हुआ है। इन कारणों से असमानता में उत्तरोत्तर वृद्धि होना अनिवार्य दिखता है।

*एक तरफ स्टीम इंजिन से चलने वाली कपड़ा मिलें लगाई जा रही थीं और दूसरी तरफ श्रमिक भूखों मर रहे थे। इन फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में उत्पादन हुआ और उद्यमी अमीर हो गए। श्रमिक के वेतन में कटौती और उद्यमी की आय में वृद्धि साथ–साथ हुई। भारत एवं चीन आज इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दोनों देशों में असमानता में भारी वृद्धि हो रही है और साथ–साथ आर्थिक विकास दर चरम पर है।*

असमानता में वृद्धि के साथ–साथ गरीबी उन्मूलन संभव है, जैसे जमींदार द्वारा बंधुआ मजदूर को रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध करा दिए जाएं तो गरीबी दूर हो जाएगी परंतु असमानता बनी रहेगी। असमानता में वृद्धि के साथ–साथ गरीबी में वृद्धि भी संभव है, जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में असमानता के साथ–साथ गरीबी का भी विस्तार हुआ था तथा अफ्रीका के रुआंडा एवं सोमालिया आदि देशों में असमानता के साथ–साथ भुखमरी व्याप्त है। अतः असमानता में वृद्धि के साथ–साथ गरीबी उन्मूलन हो सकता है और नहीं भी।

वर्तमान समय में आर्थिक चिंतन की मुख्यधारा असमानता में वृद्धि के साथ–साथ गरीबी उन्मूलन की नीति को अपना रही है। उसका मानना है कि बढ़ती असमानता की अनदेखी की जाए और ध्यान गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित किया जाए, जैसे रोजगार गारंटी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सस्ता अनाज एवं किसानों की ऋण माफी आदि कार्यक्रमों के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके पीछे यह सोच है कि गरीबी दूर होने से आम आदमी को राहत मिलेगी और वह बढ़ती

असमानता से उद्वेलित नहीं होगा।

मेरी समझ से यह सोच टिकाऊ नहीं है। गरीबी उन्मूलन के बावजूद बढ़ती असमानता समाज को विखंडित करेगी। वास्तव में, गरीबी उन्मूलन से गरीब की असमानता का विरोध करने की शक्ति में वृद्धि होती है, जैसे बस्तर आदि क्षेत्रों में गरीबी पहले से कम हुई है। वहां रोजगार गारंटी एवं शिक्षा आदि का विस्तार हुआ है, लेकिन इन क्षेत्रों में पहले शांति थी और आज नक्सलवादी गतिविधियां पनप रही हैं। कारण यह कि भूखा आदमी विद्रोह करने की क्षमता नहीं रखता। बीपीएल के सस्ते अनाज से पेट भर जाने के बाद उसे सड़क पर दौड़ता सब्जी से भरा ट्रक खटकने लगता है। बढ़ती असमानता आर्थिक विकास में भी बाधा है। बाजार मे माग उत्पन्न नहीं होती, जैसे देश के 99 प्रतिशत लोग 100 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर अपना पेट भर रहे हों तो रफ्रीजरेटर, टेलीविजन एवं मोटर साइकिल की माग कम ही उत्पन्न होगी। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि आम आदमी की खपत में भारी वृद्धि हो। यदि अमीरों द्वारा कमाए गए लाभ का वितरण नहीं होगा तो उनकी अमीरी ध्वस्त हो जाएगी। उसी तरह जैसे जमींदार के किले में लोग काम करने को न जाएं तो वह भूतों का डेरा बन जाता है। गरीबी उन्मूलन के फार्मूले में तीसरी समस्या काम करने के प्रोत्साहन के अभाव की है। गरीब को सहज ही भोजन मिल जाए तो श्रम करने की इच्छा नहीं रह जाती। अमेरिका आदि देशों में इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लोग बेरोजगारी भत्ते को लेकर मस्त हैं। उनकी श्रम करने की चाहत समाप्त हो गई है और समाज कुंठित हो रहा है। यदि समाज का एक बड़ा वर्ग इस प्रकार निष्क्रिय हो जाएगा तो समाज के स्थिर रहने में भारी संदेह है। इन कारणों से बढ़ती असमानता के साथ गरीबी उन्मूलन हो जाए तो भी वह सफल नहीं होगी। हमारे सामने विकट समस्या है। विकास की प्रक्रिया में असमानता में वृद्धि होती ही है। गरीबी उन्मूलन हो जाए तो भी यह असमानता विस्फोटक बन जाती है, जैसा कि बढ़ती नक्सलवादी गतिविधियों में देखा जा रहा है।

मेरी समझ से इस समस्या का एकमात्र हल सादगी एवं धर्मादा है। अमीर को चाहिए कि अपनी जीवनशैली साधारण बनाए रखें। ऐसा करने से अमीर की अमीरी गरीब को खटकती नहीं है और समाज स्थिर बना रहता है। अमीर को चाहिए कि अपनी आय का बड़ा हिस्सा गरीबों के कल्याण में लगाए, जैसे स्कूल एवं अस्पताल चलाने में, गांव की सड़क बनाने में तथा विधवाओं एवं वृद्धों के लिए आश्रम बनाने में। इस प्रकार के स्वैच्छिक पुनर्वितरण से गरीब की आय बढ़ेगी और बाजार में मांग उत्पन्न होगी। विद्यालय एवं सड़क उपलब्ध होने से गरीब को श्रम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अतः बढ़ती असमानता के साथ–साथ अमीरों द्वारा सादगी एवं धर्मादे को अपनाने से ही समाज स्थिर होगा।■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

# अब रोटी के लाले पड़ने वाले हैं

## *तीन माह में 300 रुपए कुंतल बढ़े गेहूं के दाम*

राजधानीवासियों को दाल, सब्जियों और उपभोक्ता वस्तुओं पर महंगाई की मार से छुटकारा मिलता नजर नहीं आ रहा। अब महंगाई के शिखर पर चढ़ती जा रही रोटी का निवाला आम लोगों के मुंह से दूर होता जा रहा है। तीन माह में गेहूं के दामों में 200 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी के साथ आटे के भाव 4 रुपए प्रति किलो से ज्यादा बढ़ चुके हैं। माना जा रहा है कि नवंबर–दिसंबर के दौरान रोटी और महंगी होगी।

व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में गेहूं के वायदा भाव 50 रुपए प्रति कुंतल से ज्यादा बढ़ चुके हैं और 1400 रुपए प्रति कुंतल का स्तर छूने को बेताब हैं। अक्टूबर का वायदा 1307.10 रुपए प्रति कुंतल तक पहुंचने के साथ नवंबर और दिसंबर के वायदा सौदों में भी 50 रुपए से ज्यादा का उछाल आ चुका है।

राजधानी की थोक मंडियों में तीन माहीने पहले गेहूं दड़ा के दाम 1045 रुपए से 1050 रुपए प्रति कुंतल के बीच थे। दिवाली के त्योहार पर 1225 से 1250 रुपए प्रति कुंतल तक पहुंच गए हैं। इसके चलते सामान्य आटे का कट्टा 130 से 140 रुपए से बढ़कर 180 रुपए तक पहुंच गया है। राजधानी में अच्छे आटे के दाम 22 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री विजय प्रकाश जैन ने कहा कि देश में इस बार गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। सरकारी एजेंसियों ने खरीदारी भी रिकार्ड स्तर पर की है। इसके बावजूद गेहूं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तीन माह में थोक बाजार में 200 रुपए बढ़ना सामान्य बात नहीं है। इसका सीधा कारण है कि गेहूं में बड़े सट्टेबाज सक्रिय हैं। यही कारण है कि वायदा व्यापार में गेहूं के दाम लगातार चढ़ते जा रहे हैं। पिछले तीन महीने की बात करें तो गेहूं के वायदा 300 रुपए प्रति कुंतल से ज्यादा चढ़ चुके हैं।

### गेहूं के दामों पर एक नजर

| गेहूं | 15 जून | 15 अक्टूबर |
|---|---|---|
| हाजिर | 1045 | 1250 |
| वायदा | 1060 | 1307.10 |

(रुपए प्रति क्विंटल)

# सुधार हैं या शिक्षा से मजाक

**euh"k oek**

न्यूनतम अंक सीमा कहाँ–कहाँ लागू की जाएगी? और क्या हर साल वह सीमा अलग–अलग होगी जैसा कि इन दिनों सीमित सीटों वालें कॉलेजों में छात्रों की संख्या नियंत्रित रखने के लिए बदलती रहती है। आर्थिक रूप से संपन्न और प्रतिभाशाली छात्र तो उच्च शिक्षा के लिए बाहर देशों में चले जाते हैं, दूसरी तरफ उनसे ज्यादा योग्य और दक्ष विद्यार्थी आर्थिक कारणों से आगे या अच्छे संस्थानों में नहीं पढ़ पाते।

जब कभी भारतीय मूल के वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद् या अन्य क्षेत्रों के अधिकारी विशेषज्ञों, विद्वानों को अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होता है तो दो भिन्न तरह की प्रतिक्रियाएँ होती हैं। एक प्रतिक्रिया जिसमें प्रत्येक भारतीय, शिक्षा संस्थान और सरकार का सिर गर्व से उठ जाता है और दूसरी, जब यह प्रश्न उठता है कि ऐसा हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में कार्यरत मनीषी क्यों नहीं कर पाते? दूसरी स्थिति में वह सब जिनका सिर गर्व से उठा था, बगलें झाँकने लगते हैं क्योंकि निष्क्रियता साकार झलकती है। ज्यादातर लोग इस यथार्थ को नहीं नकार पाते कि हम इन लोगों की प्रतिभा को पहचान नहीं पाए, इन्हें उचित संबल, सुविधा और वातावरण नहीं दे पाए जिसमें इन लोगों के सर्जनात्मक गुण निखर पाते। ऐसे समय सरकार और अधिकारीगण एक बार फिर शिक्षा की बात करते हैं, परन्तु असल में यह बात और चिंता केवल समाचार–पत्रों और सूचना माध्यमों तक ही सीमित रह जाती है। संकीर्णता से भरपूर सरकारी संस्थाएँ और उनके अधिकारियों का चिंतन अपनी जगह अडिग रहता है।

उन प्रतिक्रियाओं और संकीर्णताओं के बावजूद यह तथ्य अपने स्थान पर अडिग है कि प्रतिभा व गुणों को आयु और समयसीमा में नहीं बाँधा जा सकता और न ही सृष्टिकर्ता के सृजन व आविष्कार को। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब एक सामान्य विद्यार्थी ने अपने विद्यार्थी जीवन में हर परीक्षा में सामान्य प्रतिभा का परिचय दिया, लेकिन किसी खास वर्ष में ऐसा अद्भुत प्रदर्शन कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसके विपरीत यह भी देखा गया है कि सभी कक्षाओं में प्रथम आने वाला छात्र किन्हीं कारणों से बोर्ड की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, वह पिछड़ गया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों स्थितियों का विश्लेषण कोई साधारण कार्य नहीं है। पर यदि इस छात्र को आईआईटी व इसी प्रकार की किसी प्रवेश परीक्षा में मात्र एक बार कम अच्छे प्रदर्शन के कारण परीक्षा देने से रोक दिया जाए तो सचमुच उसके साथ अन्याय होगा। और रुकने की खास वजह यह हो कि अमुक मंत्री या उसके द्वारा गठित कमेटी ने एक न्यूनतम अंक सीमा निर्धारित कर शिक्षा में सुधार व उदारीकरण की वाह–वाह लूटी थी तो इसे व्यक्ति विशेष के मूल अधिकारों के साथ मानवीय व न्यायिक मूल्यों का हनन ही माना जाएगा, क्योंकि इस तरह किसी प्रतिभाशाली छात्र को कमजोर प्रदर्शन के कारण रोक देना उसके पूरे भविष्य पर ही आघात है उस कमजोर प्रदर्शन के लिए जबकि कोई तात्कालिक कारण ही जिम्मेदार रहे हों। प्रश्न उठता है कि क्या इसी प्रकार प्रशासनिक सेवा और अन्य सेवाओं की परीक्षा के लिए भी एक विशेष स्तर पर प्राप्तांकों को मान्यता दी जाएगी?

भारत में अंग्रेजी शासनकाल के नियमों में उदारीकरण के स्थान पर केंद्रीकरण अधिक हुआ है। केंद्रीकरण अर्थात संभावनाओं के एक खास दायरे में ही सिमट जाने की स्थिति। उस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ से लेकर उच्च स्तर तक छात्रों के लिए ऐसी कसौटियाँ निर्धारित की गईं जिनका उसकी प्रतिभा के विकास से ज्यादा ताल्लुक नहीं था, जैसे स्कूल में प्रवेश की आयु, बोर्ड परीक्षा के लिए आयु सीमा, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा, जाति, आर्थिक स्थिति, विषयों के चुनाव पर प्राप्तांकों की सीमा और विषयों के चुनाव पर प्रतिबंधन आदि।

हर बार यह विचार किया जाता है कि शिक्षा में सुधार व उदारीकरण कर इसे बंधन मुक्त किया जाएगा ताकि सभी देशवासी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त कर सकें। शिक्षा सुविधाएँ आम व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध हों। सभी स्कूलों के वातावरण व शिक्षा स्तर को सुधारा जाए। पर वास्तविकता यह है कि देश के अच्छे–से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे छात्र को भी घर पर निजी शिक्षा की सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो गया हैए जो बहुत महँगा है। कहीं ज्यादा अच्छा होता यदि मानव संसाधन मंत्री कहते कि प्रत्येक स्कूल को बारहवीं कक्षा के साथ–साथ अन्य प्रवेश परीक्षाओं की भी तैयारी करनी होगी। यदि उनका मंत्रालय सरकारी स्कूलों में समुचित अध्यापक और सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास कर किसी विषय विशेष और आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था कर पाता तो सभी सराहते। परंतु यह कहना कि 80 से 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति होगी, न तो युक्तिसंगत प्रतीत होता है साथ ही शिक्षा के अधिकार का हनन करता है। हमारे देश में प्रवेश प्रतियोगिता के साथ–साथ तरह–तरह के आरक्षण भी हैं। ऐसी स्थिति में न्यूनतम अंक सीमा कहाँ–कहाँ लागू की जाएगी? और क्या विभिन्न श्रेणियों के लिए हर साल वह सीमा अलग–अलग होगी जैसा कि इन दिनों सीमित सीटों वाले कॉलेजों में छात्रों की संख्या नियंत्रित रखने के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा बदलती रहती है।

आर्थिक रूप से संपन्न और प्रतिभाशाली छात्र तो उच्च शिक्षा के लिए बाहर देशों में चले जाते हैं, दूसरी तरफ उनसे ज्यादा योग्य और दक्ष विद्यार्थी आर्थिक कारणों से आगे या अच्छे संस्थानों में नहीं पढ़ पाते। उनके लिए बाहर देशों में पढ़ाई के लिए जाना तो सपना ही रह

*शेष पृष्ठ 26 पर* ➡

## छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर विशेष

# शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ रहा देश में अव्वल

*लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को आई.बी.एन. डायमंड स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया*

N त्तीसगढ़ ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पूरे देश में अपना परचम लहराया है । राज्य में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में किए गये बेहतर कार्यों से हासिल परिणामों के आधार पर दोनो वर्गों में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान पाने का गौरव हासिल किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने एक भव्य और गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को दोनों क्षेत्रों में प्रथम आने पर पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवसर पर गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, नागालैण्ड, सिक्किम, मेघालय के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री और अनेक राज्यों के मंत्रीगण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ को अवार्ड देने का निर्णय छह सदस्यीय निर्णायक मंडल ने किया जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डॉ. विमल जालान, फिक्की के महासचिव श्री डॉ. अमित मित्रा, आई.आई.एम अहमदाबाद के पूर्व डायरेक्टर डॉ. बकुल ढोलकिया, लेखक श्री गुरचरन दास और प्रोफेसर पुष्पेश पंत शामिल थे।

समारोह के दौरान देश के विकास में राज्यों की बढ़ती भूमिका विषय पर आयोजित चर्चा के दौरान यह कहा गया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य ने गत 6 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो प्रगति की है उसने देश के नीति निर्धारकों और योजनाकारों को चकित कर एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। छत्तीसगढ़ ने देश की राजनीति को एक रास्ता दिखाया है कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर विकास के मुद्दे पर भी पुनः चुनाव जीता जा सकता है। समारोह में सम्मान ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। उन्होंने सभी प्रबुद्धजनों से आग्रह किया कि वे छत्तीसगढ़ को केवल नक्सल समस्या के चश्में से न देखें बल्कि गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये सकारात्मक कार्यों के परिणामों को देख उन पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक और खनिज संपदा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश के इस्पात उत्पादन में 30 प्रतिशत और सीमेन्ट उत्पादन में 26 प्रतिशत योगदान देता है। हमारे पास देश का सबसे बेहतर बाक्साईट है। वर्ष 2015 तक हम 15 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन में सक्षम होकर देश की बिजली समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे । यही नहीं हम 37 लाख परिवारों को एक और दो रूपये किलो चावल, निःशुल्क नमक और आदिवासियों को चरण पादुका प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने यह तय किया है कि वर्ष 2020 में हम देश के सबसे बेहतर तीन विकसित राज्यों में अपना स्थान बना लेंगे। नक्सल समस्या पर पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता ने ही रास्ता दिखाया है और अब पूरा देश हमारे प्रयासों में हमारे साथ खड़ा है। समारोह में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एन. बैजेन्द्रकुमार और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री विक्रम सिसोदिया भी उपस्थित थे। ■

# भोजन का अधिकार हुआ धरातल पर साकार

**LojkT; d|ekj**

Nत्तीसगढ़ के लगभग 37 लाख गरीब परिवारों को आठ जुलाई की उस सुबह का बड़ी बेताबी से इन्तजार है, जब सूरज की पहली किरण उनके लिए देश के अन्य सभी राज्यों के मुकाबले सबसे कम कीमत पर चावल और निःशुल्क नमक मिलने का पैगाम लेकर आएगी। इस दिन राज्य की दस हजार 455 उचित मूल्य दुकानों में 'चावल उत्सव' एक साथ मनाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य के गरीबों को किफायती दर पर चावल देने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अप्रैल 2007 से संचालित की जा रही है। शुरूआती दौर में इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 19 लाख गरीब परिवारों को तीन रूपए किलो में चावल 35 किलो चावल दिया जा रहा था। इस बीच डॉ. रमन सिंह की सरकार ने योजना में सभी वर्गों के गरीबों को शामिल करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री का यह विचार था कि गरीब सिर्फ गरीब होता है और गरीबी जाति बंधन को नहीं देखती। गरीबों के दुख–दर्द को जाति बंधन से ऊपर उठ कर ही दूर किया जा सकता है। डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की सातवीं वर्षगांठ पर एक नवम्बर को राज्योत्सव 2007 में इस योजना में जाति बंधन को खत्म करते हुए सभी वर्गों के गरीबों को शामिल करने का ऐलान किया। उनकी इस घोषणा के अनुरूप जनवरी 2008 से इस योजना का विस्तार हुआ और अब राज्य के 37 लाख गरीबों को उचित मूल्य दुकानों में राशन कार्ड पर केवल तीन रूपए किलो में हर महीने 35 किलो चावल मिलने लगा, लेकिन इस देशव्यापी आर्थिक संकट और महंगाई के इस दौर में राज्य के गरीबों को और भी ज्यादा राहत पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी पहल करते हुए डॉ. रमन सिंह की सरकार ने अन्त्योदय श्रेणी के सात लाख 19 हजार परिवारों को महज एक रूपए में और शेष करीब 30 लाख अन्य गरीब परिवारों को सिर्फ दो रूपए किलो में चावल देने का ऐलान किया है। चावल उन्हें कुपोषण से बचाएगा। डॉ. रमन सिंह की भी यह स्पष्ट मान्यता है कि 'धान के कटोरे' के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के मेहनतकश गरीबों को धान से बनने वाला चावल कम कीमत पर मिलना चाहिए। यह उनका अधिकार भी है। यह भी गौरतलब है कि डॉ. रमन सिंह देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए 'भोजन के अधिकार' की देश भर में हो रही किताबी और अखबारी चर्चाओं से ऊपर उठकर मेहनतकशों के इस अधिकार को अपनी इन योजनाओं के जरिए धरातल पर सबसे पहले साकार किया है। इन योजनाओं से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी एक नया अर्थ मिला है।

मुख्यमंत्री ने इन सभी गरीबों को बिचौलियों के शोषण चक्र से बचाने और आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा देने के लिए पांच वर्ष पहले 25 पैसे किलो में जिस 'अमृत' नमक वितरण की शुरूआत की थी अब उन्होंने यह नमक निःशुल्क देने की घोषणा कर दी है। खुले बाजार में कहीं पन्द्रह–सोलह रूपए तो कहीं बीस रूपए और 25 रूपए तक प्रति किलो के भाव से बिक रहा चावल छत्तीसगढ़ के गरीबों को अगर केवल एक रूपए और दो रूपए किलो में मिले, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आकर्षक पैकेटों में दस–पन्द्रह रूपए किलो में बिकने वाला नमक उसी तरह की पैकेजिंग में छत्तीसगढ़ के गरीबों को अब तक 25 पैसे किलो में मिलने के बाद अगर अब निःशुल्क मिलने लगे तो यह सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनशीलता का एक जीता–जागता दुर्लभ उदाहरण होगा। छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों के लिए बाजार से महंगा चावल खरीदकर उन्हें बेहद सस्ते में सुलभ करा रही है।

कोई बताए तो सही कि आज देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां गरीबों को किसी सरकार की ओर से नमक निःशुल्क और चावल सिर्फ एक रूपए और दो रूपए किलो में दिया जा रहा हो ? इस प्रश्न के जवाब में देश के नये राज्य छत्तीसगढ़ की तस्वीर उभरती है। रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने 'दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहि काहुहि व्यापा।।' जैसी पंक्तियों से जिस रामराज्य का चित्रण किया था, संत कबीरदास ने 'सांई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा न रहूं, साधू न भूखा जाय।।' कहकर जिस आदर्श समाज व्यवस्था की परिकल्पना की थी, डॉ. रमन सिंह की सस्ते चावल और निःशुल्क नमक की कल्याणकारी योजनाओं से यह संकेत मिलता है कि छत्तीसगढ़ उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहरहाल राज्य के गरीबों को 8 जुलाई के उस ऐतिहासिक दिन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है जब उनके घर छत्तीसगढ़

सरकार की ओर से देश का सबसे सस्ता चावल पहुंचेगा और वे निःशुल्क अमृत नमक के जरिए अपने भोजन को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकेंगे।

**आसानी से होगा गुजारा**

राज्य सरकार की इन ऐतिहासिक योजनाओं को लेकर प्रदेश के गरीबों में काफी उत्साह और उत्सुकता है। जांजगीर–चाम्पा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ स्थित ग्राम पेण्ड्री निवासी अनुसूचित जाति के 65 वर्षीय बुजुर्ग श्री बैजूराम और उसी गांव के श्री मोहन लाल की पत्नी श्रीमती राजकुमारी चौहान अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्ड धारक परिवारों के सदस्य हैं। योजना का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि एक रूपए किलो में चावल मिलने पर अब वे अपनी मेहनत मजदूरी की शेष राशि बच्चों की पढ़ाई–लिखाई सहित दाल, तेल और कपड़े आदि की जरूरतों पर आसानी से खर्च कर सकेंगे। जांजगीर–चाम्पा जिले के ही रिक्शा चालक शुकलाल कश्यप केसरिया राशन कार्ड धारक हैं जिन्हें दो रूपए किलो में चावल मिलेगा। उनकी पत्नी श्रीमती केंवरा बाई कहती हैं कि अब इतनी कम कीमत पर हर महीने चावल मिलने पर वे अपने छह सदस्यों वाले परिवार का गुजारा आसानी से कर सकेंगे। बिलासपुर जिले के विकासखण्ड मस्तूरी के ग्राम धनगवां निवासी गेंदराम कहते हैं कि उन्हें प्रतिदिन अपने घर चूल्हे जलाने के लिये पहले सोचना पड़ता था, लेकिन राज्य सरकार ने उनका बखूबी ख्याल रखा। वे कहते हैं कि जुलाई से तो अब उनके मजदूरी की राशि का आधा बच जायेगा और उसका उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई व उनके लालन–पालन के लिये करेंगे। ग्राम धनगवां के ही रामफल भारद्वाज कहते हैं कि चाउंर वाले बाबा डॉ. रमन सिंह ने उन्हें अब तक सिर्फ तीन रूपए किलो में चावल का एक बड़ा सहारा दिया और अब हमारे मुख्यमंत्री हम जैसे गरीबों की तकलीफों को समझकर इसकी कीमत और भी कम कर रहे हैं। अब हमें दो रुपये किलो में चावल मिलेगा। मजदूरी की राशि से काफी हिस्से की बचत होगी और उस राशि से हम पौष्टिक भोजन के लिए सब्जी भी खरीद सकेंगे।

**रोजगार और सस्ता चावल है तो हम गांव**

*शेष अगले पृष्ठ पर* ➡

# विकास की रोशनी से कोई भी वंचित नहीं रहेगा : डॉ. रमन

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में विकास की रोशनी से समाज का कोई भी वर्ग और प्रदेश का कोई भी कोना अछूता नहीं रहेगा। गांव, गरीब और किसानों सहित हर मेहनतकश तबके के जीवन में सुख–समृद्धि का आलोक फैलाने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है।

डॉ. सिंह ने जिला मुख्यालय महासमुंद में लगभग ग्यारह करोड़ रूपए के विभिन्न विकास प्रकल्पों का लोकार्पण और भूमि–पूजन करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए। उन्होंने जिले की जनता को दीपावली और भाई–दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉ. रमन सिंह ने इस मौके पर हाई स्कूल मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में कहा कि विगत छह वर्ष में आम जनता के सहयोग से प्रदेश में प्रारंभ विकास योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में राज्य शासन को अच्छी सफलता मिली है। विकास की गति बढ़ी है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जनता के सहयोग से छत्तीसगढ़ बहुत जल्द भारत के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार सभी स्तरों पर हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों को एक रूपए और दो रूपए किलो में चावल, निःशुल्क नमक, किसानों को खेती के लिए सिर्फ तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण सुविधा, पांच हार्सपावर तक सिंचाई पम्पों के लिए छह हजार यूनिट निःशुल्क बिजली, स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और लाखों गरीब परिवारों को एकलबत्ती योजना में तीस यूनिट निःशुल्क बिजली देने की योजनाएं प्रारंभ कर राज्य सरकार ने वास्तव में समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को उनका अधिकार दिलाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों की तंग बस्तियों में निवास कर रहे ढाई लाख गरीब परिवारों को स्वच्छ पेयजल के लिए निःशुल्क नल कनेक्शन देने का निर्णय लिया है और इसके लिए भागीरथी नल–जल योजना शुरू कर दी गयी है। इस योजना पर लगभग 72 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महासमुंद जिले में महानदी के किनारे संचालित फर्शी पत्थर उद्योग से जुड़े लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज के कार्यक्रम में महासमुंद नगर पालिका क्षेत्र की तंग बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन देने के लिए भागीरथी नल–जल योजना का शुभारंभ करते हुए वहां महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र) का शिलान्यास भी किया। इस भवन के निर्माण में लगभग दो करोड़ रूपए की लागत आएगी। डॉ. सिंह ने इस मौके पर जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम बकमा में दो करोड़ 34 लाख रूपए, गाड़ाघाट दो करोड़ 40 लाख रूपए और अमलोर में 69 लाख रूपए की लागत से निर्मित तीन एनीकटों और ग्राम परसाडीह में 65 लाख 14 हजार रूपए की लागत से निर्मित स्टाप डेम का लोकार्पण किया।

उन्होंने कहा कि स्टाप डेम सहित तीनों एनीकटों से जहां ग्रामीणों को निस्तारी और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहीं भू–जल स्तर भी बढ़ेगा डॉ. सिंह ने कार्यक्रम में महासमुंद शहर के शीतली नाले पर एक करोड़ 53 लाख रूपए की लागत से और झारा–रायखेड़ा मार्ग पर दैहारी नाले में एक करोड़ 23 लाख रूपए की लागत से निर्मित पुलों का भी लोकार्पण किया। ■

**क्यों छोड़ें ?**

विकासखण्ड लोरमी के ग्राम गुनापुर के प्रमादी व सुरेश दोनो कहते हैं कि पहले मजदूरी के लिये उन्हें जिले से बाहर जाना पड़ता था। क्योंकि उन्हें अपना व बच्चों का पेट पालना पहले मुश्किल था। परन्तु राज्य सरकार ने हमारे गांव में रोजगार गारंटी के कार्य खोले और सस्ते चावल की व्यवस्था की है तो हम रोजी–रोटी के लिए गांव छोड़कर दूर क्यों जाएं ? खुशी से वे कहते हैं कि अब तो सरकार उन्हें बच्चों की तरह पाल रही है। जुलाई माह से वे दो रुपये किलो में चावल खरीदेंगे।

बिलासपुर जिले के ग्राम लगरा की बरमतबाई कहती हैं कि डॉ. रमन सिंह ने गरीबों का ख्याल रखा है।

**कभी सोचा भी नहीं था**

उधर राज्य के आदिवासी बहुल नक्सल हिंसा पीड़ित बस्तर जिले के गांवों और शहरों के गरीबों में भी सस्ते चावल और निःशुल्क नमक की इस योजना को लेकर भारी उत्सुकता देखी जा रही है। जिले में फरसगांव तहसील के ग्राम चरकई के राशनकार्ड धारक अन्त्योदय योजना के हितग्राही श्री अमरूराम पिता बुड़कू यह कहते है कि आज के जमाने में मुझे एक रूपये प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा। यह मैने कभी सोचा भी नहीं था। मैं पहले पेट के भूख की चिंता में दिन–रात घुलता था। अब यह चिंता सरकार ने हल कर दी। मैं अब बहुत खुश हूं कि मुझे एक रूपये की दर से चावल मिलेगा। मेरी मेहनत मजदूरी का पैसा अब और भी अधिक बचेगा उससे मैं स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिऊंगा। अन्त्योदय कार्ड धारक होने के कारण ग्राम कलचा की श्रीमती योगिता देवांगन पति जयराम के परिवार को भी सिर्फ एक रूपए किलो में चावल मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक रूपये में आज कोई भी खाने की चीज मुश्किल से ही मिलती है, लेकिन डॉ. रमन सिंह की सरकार ने गरीबों के लिए मात्र एक रूपये प्रति किलो की दर से चावल देने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है, यह तो हमारे लिए और मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए खुशी की बात हैं। जिले के बडेराजपुर के ग्राम जोड़ेकेरा की श्रीमती तुषारीबाई पति खंडू ने भी इसी तरह के विचार मुखरता से प्रकट करते हुए कहा कि मै डा. रमन सिंह को जानती हूं, वो हमारी फिक्र करते हैं, इसीलिए तो हमें एक रूपये और दो रूपये किलो में चावल देने की बढ़िया व्यवस्था की है।

**चावल इतना सस्ता - मिला खुशहाल जीवन का रस्ता**

मुख्यमंत्री के गृह जिले कबीरधाम (कवर्धा) में भी एक रूपए और दो रूपए किलो चावल और निःशुल्क नमक की योजनाओं को लेकर लोगों में उत्साहजनक प्रतिक्रिया है। जिला मुख्यालय कवर्धा से लगभग 60 किलोमीटर पर हरे–भरे जंगलों में बसे बैगा आदिवासी बहुल ग्राम लूप निवासी इतवारी राम धुर्वे कहते हैं – 'हमर छत्तीसगढ के डॉ रमन के सरकार हर हमन ल पालत पोंसत हावय, जेकर खातिर हम गरीब मन बर दो रुपिया किलो में चांऊर देवत हे। सरकार के तरफ से दो रुपिया किलो में चांऊर से हमर जैसी गरीब के भला होवथे अऊ हमर राशन पानी के चिंता हर दूर हो जाथे। अऊ महागरीब ल एक रूपया किलों घलो में चाऊर मिलत हावय'। ईतवारी राम के साथ–साथ लूप के भादू सिंह, जुगत सिंह, सरोदादर के भकोल सिंह, लमतू बैगा, बैगा, ग्राम दुलदुला के धीरू और बैसाखू बैगा आदिवासियों को भी सस्ते चावल की इस क्रांतिकारी योजना से एक खुशहाल जीवन की राह मिली है। ईतवारी राम का कहना है कि हमारे गांव के राशन की दुकान में मिट्टी तेल और शक्कर भी मिलता है, जिसे खरीदकर हम लोंग उपयोग में लाते हैं। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान से साफ बढिया और सस्ते कीमत में चावल मिल रहा है। चावल खत्म हो जाने से फिर से चावल दूसरे महीने हमें बराबर मिल जाता है और केवल चावल ही नहीं बल्कि मिट्टी तेल, छत्तीसगढ अमृत नमक भी मिलता है, जिसका उपयोग हम सभी कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना की चावल पाकर हम सभी गरीब प्रसन्न है और हमें राशन की चिंता से मुक्ति मिली। सरकार के इस उपकार को हम कभी नहीं भुला सकते।

**घर खर्च चलाना अब नहीं मुश्किल**

राज्य के औद्योगिक शहर कोरबा के नगर निगम क्षेत्र में पथर्रीपारा वार्ड के बेहद गरीब महिला 45 वर्षीय श्रीमती हेमबाई गभेल ने बताया कि सिर्फ रोजी–मजदूरी के भरोसे अपने चार सदस्यीय परिवार का पालन पोषण बहुत कठिन था, किंतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना ने उनकी इस समस्या का काफी हद तक समाधान कर दिया है। हेमबाई गभेल पति स्वर्गीय हेमलाल गभेल के पास पैतृक जमीन नहीं के बराबर है। परिवार में उनके अलावा उनका लड़का नरेंद्र गभेल बहू श्रीमती सुरेश्वरी गभेल तथा नातिन श्रेया सहित कुल चार सदस्य हैं। मंहगाई के कारण केवल अनियमित मजदूरी के भरोसे उन्हें परिवार के सदस्यों को पेट भर भोजन उपलब्ध कराने काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उन्होने कहा कि गरीबी के कारण घर का खर्च चलना मुष्किल था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना उनके परिवार के लिए वरदान साबित हो रही है। पथर्रीपारा के ही अन्त्योदय कार्डधारी सुकृतदास ने बताया कि उन्हें अभी 3 रूपये की दर से 35 किलो चावल प्राप्त हो रहा है। सुकृतदास को इस बात की जानकारी है कि आगामी 8 जुलाई से उन्हें भी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत 1 रूपये प्रतिकिलो की दर से 35 किलोग्राम चांवल प्राप्त होगा। सुकृतदास

अभी मजदूरी तथा साग–सब्जी बेचकर अपने 4 सदस्यीय परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुकृतदास ने कहा कि एक रूपये किलो में 35 किलो चावल मिलने से उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में और अधिक राहत मिलेगी।

**मेरे राशन कार्ड पर भी लगी एक रुपए की मुहर**

रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड स्थित ग्राम पंचायत मांढर निवासी अंत्योदय अन्न योजना के हितग्राही 70 वर्षीय श्री पुनऊराम ने इस योजना की जानकारी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अब एक रुपए किलो की दर से हर माह 35 किलो चावल मिलेगा। मेरे कार्ड में एक रुपए किलो चावल योजना की मुहर लग गई है। यह कहते हुए उन्होंने उत्साह के साथ अपना राशन कार्ड भी दिखाया। श्री पुनऊराम ने यह भी बताया कि उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर माह ग्राम पंचायत कार्यालय से तीन सौ रुपए पेंशन भी मिलती है। अब 35 रुपए में उनके माह भर के चावल का इंतजाम हो जाएगा और बचत के पैसे दूसरे जरुरतों में काम आएंगे। वे पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तीन रुपए किलो चावल योजना के लिए सरकार को धन्यवाद देना नहीं भूलते। श्री पुनऊराम कहते हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने हम गरीबों के दुख–दर्द को महसूस करके सस्ते चावल की योजना लागू की और हमारे दो वक्त के भरपेट भोजन की व्यवस्था कर दी।

**चांउर वाले बाबा के चावल का ही सबसे बड़ा सहारा**

राजधानी रायपुर की गरीब बस्ती कुकुरबेड़ा के निवासी श्री श्याम तांडी ने बताया कि उनके परिवार के लिए चाऊंर वाले बाबा का चावल ही सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने बताया कि अब तक तीन रूपए में 35 किलो चावल मिलता था, सात सदस्यीय परिवार को यह चावल लगभग पन्द्रह दिन चलता है, अब दो रूपए किलो में चावल मिलने पर थोड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि वे रिक्शा चलाकर अपने परिवार की गुजर–बसर करते हैं, आटो और सिटी बस चलने के कारण उनकी आमदनी भी कम हो गई है। अब मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता से मिलने वाला चावल ही उनका बड़ा सहारा है। कुकुरबेड़ा के ही श्री श्यामलाल सोना मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। कभी–कभी मजदूरी नहीं मिलने पर उनके परिवार को भूखे रहने की नौबत आ जाती थी, लेकिन जब से मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना का चावल मिलना शुरू हुआ है, तब से उनके परिवार के सामने कभी फांके की नौबत नहीं आई। उन्होंने बताया कि सस्ता चांवल मिलने से कुछ पैसे बच जाते हैं, इससे वह अपने बच्चे को आठवीं में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले बाजार से उन्हें पन्द्रह से सोलह रूपए में चावल खरीदना पड़ता था, राशन दुकान से सस्ता चावल मिलने पर उन्हें प्रति किलो चौदह–पन्द्रह रूपए की बचत हो जाती है।

राज्य सरकार ने गरीबों के व्यापक हितों को ध्यान में रख कर सस्ते चावल और निःशुल्क नमक की इन योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और भी अधिक कसावट लाने की ठोस पहल की है। राशन दुकानों के स्तर पर स्थानीय पंच सरपंचों, वार्ड पार्षदों और प्रमुख नागरिकों की निगरानी समितियां वितरण व्यवस्था पर पैनी नजर रखती हैं। जिला और विकासखंड स्तर पर भी निगरानी समितियां कार्यरत हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में हाईटेक संचार प्रणाली का इस्तेमाल भी इन योजनाओं की निगरानी के लिए किया जा रहा है। वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जनवरी 2008 से प्रदेशवासियों को राजधानी रायपुर में कॉल सेंटर की भी एक बड़ी सुविधा दी है, जहां निःशुल्क टेलीफोन नम्बर 1800–233–3663 पर राज्य के किसी भी कोने से टेलीफोन कर कोई भी नागरिक किसी भी राशन दुकान के बारे में अपनी समस्या अथवा शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां खाद्य विभाग द्वारा अपनी जनभागीदारी वेबसाईट भी शुरू की गई है, जिसमें कोई भी नागरिक अपना निःशुल्क पंजीयन करवा कर ई–मेल के

जरिए विभाग को अपनी शिकायत या अपने सुझाव भेज सकता है। उनको निराकरण की जानकारी ई–मेल के जरिए भी दी जाती है। इस वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजी.एनआईसी. इनसिटीजन में पंजीयन कराने वाले नागरिकों को उनके मोबाईल फोन पर उन गाड़ियों की जानकारी एस.एम.एस के जरिए मिल सकती है, जिन्हें राशन दुकानों में सामग्री पहुंचाने का काम सौंपा जाता है। गाड़ियों में भेजी जा रही राशन सामग्री की मात्रा, ट्रक नम्बर और उसके चालान नम्बर की जानकारी भी एस.एम. एस. के माध्यम से नागरिकों को दी जाती है। छत्तीसगढ़ में जनभागीदारी से संचालित इस निगरानी तंत्र में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और उसके अन्तर्गत लाखों राशन कार्डधारकों के हितों को सुरक्षा की एक पुख्ता और पूरी गारंटी मिली है। ■

कमल संदेश

# नवा अंजोर से गरीबों के जीवन में नई रोशनी

&yfyr pronh

Çदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों के बहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना (नवा अंजोर) गरीबी उन्मूलन की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 16 जिलों के 40 विकासखण्डों के चयनित 2023 ग्राम पंचायतों में जून 2004 से संचालित की जा रही है। यह परियोजना पूरे देश में अपने ढंग़ का एक अभिनव प्रयास है, जिसमें एक लाख से अधिक ग्रामीण गरीब परिवारों को समहित समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस परियोजना से लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लोगों की आमदनी बढ़ने के साथ ही जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब परिवारों का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ा है। परियोजना के तहत तैयार उत्पादों के समुचित बाजार व्यवस्था और कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विश्व बैंक की मध्यावधि समीक्षा में परियोजना क्रियान्वयन लागत को पूरे विश्व में संचालित आजीविका संवर्धन परियोजनाओं में सबसे अधिक कास्ट इफेक्टिव माना गया है। परियोजना की कुल लागत 522 करोड़ रूपए है। इसमें से 262 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा परियोजना की अवधि में एक साल की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य में यह परियोजना अब 31 मार्च 2010 तक संचालित होगी। परियोजना के तहत बीस हजार समहित समूहों का गठन कर एक लाख परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध अब तक 20 हजार 760 समहित समूह गठित कर एक लाख 11 हजार 858 परिवारों को 188 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता स्वी.त की जा चुकी है। यह उपलब्धि लक्ष्य के शतप्रतिशत से अधिक है। परियोजना के माध्यम से मिली आर्थिक सहायता से समहित समूहों के सभी परिवार आर्थिक स्वावलबंन की ओर अग्रसर है। इस प्रकार यह परियोजना राज्य के ग्रामीण गरीब और साधनविहीन लोगों की तकदीर और तस्वीर सफलतापूर्वक बदल रही है।

नवा अंजोर परियोजना के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकताओं का स्थानीय स्तर पर पता लगा कर ग्रामीण गरीबों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे है। गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में लाख उत्पादन से रोजगार की काफी संभावनाओं को ध्यान में रखकर सेमीलता, कुसम और पलाश के पौधों का अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जा रहा है। गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मेंहदी, आंवला और औषधीय पौधों की ज्यादा से ज्यादा खेती पर जोर दिया जा रहा है। परियोजना के तहत दसवीं फेल 18 से 35 वर्ष आयु समूह के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए उनकी योग्यता के अनुसार कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर प्रतिष्ठित संस्थाओं में नौकरी उपलब्ध कराने की विशेष योजनाएं भी प्रारंभ कर दी गई है। सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा राजमिस्त्री, टेलरिंग, इलेक्ट्रीशियन, मोटर ड्रायविंग, कम्प्यूटर आपरेटर, भारी मशीनों के संचालन, निजी सुरक्षा सेवा आदि के प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं का चयन कर दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता जैसे महानगरों में भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण के लिए राज्य के सात विकासखण्डों में प्रारंभिक तौर पर पायलेट प्रोजक्ट प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें रायपुर जिले का तिल्दा, बस्तर का बस्तर, राजनांदगांव का डोगरगांव, बिलासपुर का कोटा, सरगुजा का ओडगी, दुर्ग का गुण्डदेही और कोरबा जिले का विकासखण्ड करतला शामिल है। इन सभी कौशल उन्नयन कार्यक्रम के लिए जिला पंचायतों के माध्यम से नामांकन

और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर युवाओं का चयन किया जाएगा।

परियोजना के माध्यम से लाभान्वित परिवारों में अनुसूचित जाति के 40 हजार 295, अनुसूचित जनजाति के 15 हजार 407, अन्य पिछड़ा वर्ग के 52 हजार 312 और सामान्य वर्ग के तीन हजार परिवार शामिल है। लाभान्वित परिवारों में 26 हजार 212 महिलाएं है। स्वीकृत समहित समूह उप–परियोजना की गतिविधियों में ग्रामीण सेवा के चार हजार 715, कृषि एवं उद्योग की पांच हजार 29, पशुपालन और परम्परागत आधारित पांच हजार 750 कार्य शामिल है। नवा अंजोर परियोजना के चयनित गांवों में विकास के लिए 63 करोड़ 03 लाख रूपए की लागत के स्वीकृत तीन हजार 347 कार्यो में से दो हजार 765 कार्य पूरे हो गए हैं। इन ग्राम पंचायतों में सीमेंट कांक्रीट सड़क, पुल–पुलिया, पेयजल व्यवस्था, सेवा केन्द्र, मुक्तिधाम, विद्युत विस्तार, सामुदायिक भवन, आगंनबाड़ी, खेल–मैदान, स्कूल भवन, ड्रेनेज सिस्टम सुधार, निर्मलाघाट निर्माण के कार्य शामिल है। नवा अंजोर परियोजना द्वारा 192 भवनविहीन ग्राम पंचायतों में चार करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है।

परियोजना के तहत अब तक दो हजार 517 नलकूप खनन, 856 लघु सिंचाई योजना और 839 सिंचाई कुओं का निर्माण कराया गया है। इससे 25 हजार से अधिक गरीब किसान परिवारों को 27 हजार एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे किसानों को प्रतिवर्ष 50 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। जो किसान पहले अपनी फसल के लिए वर्षा पर आश्रित थे, आज उनके पास स्वयं के सिंचाई साधन होने से वे साल में दो फसल ले रहे है। किसानों में इससे काफी हर्ष व्याप्त है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत व्यवसाय करने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सवा लाख रूपए की लागत से ग्राम पंचायतों में व्यवसाय करने के लिए 286 ग्रामीण सेवा केन्द्रों

का निर्माण कराया गया है। परियोजना के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों में डेयरी, मुर्गीपालन, सूकर पालन, बकरी पालन और मछली पालन से 25 हजार 500 परिवार लाभान्वित हुए हैं। पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय से प्रतिवर्ष 85 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आय हो रही है। परम्परागत व्यवसायों में राजमिस्त्री, कुम्हारी, बढ़ईगिरी, बुनकर, चर्म उद्योग आदि से 25 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हुए है। ग्रामीण लघु उद्योग और सेवा क्षेत्र से स्वरोजगार जैसे–टेन्ट हाउस, पापड़, बड़ी, आचार, सुरक्षागार्ड, सायकल स्टोर्स, लघु वनोपज संग्रहण, आटा चक्की, किराना दुकान, कबाड़ी दुकान, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, बेलमेटल तथा हस्तशिल्प कार्य की इकाईयां 20 हजार 500 से अधिक परिवारों द्वारा स्थापित की गई हैं। इन परिवारों को 175 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो रही है। आर्थिक गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण एवं बाजार व्यवस्था के लिए पंचायत स्तर पर दो हजार 23 आजिविका संवर्धन समितियों का गठन किया गया है।

ग्राम पंचायत उप–परियोजना के तहत परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में मूलभूत अधोसंरचना विकास के तीन हजार 377 कार्य कराए गए है। इनमें सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण के दो हजार 52, नलकूप और पेयजल सुविधा के 219, महिलाओं के लिए 145 निर्मलाघाट, पुल–पुलिया 251, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भवन और गोदाम 38, सामुदायिक भवन 53, विद्युत विस्तार के 42 और नाली निर्माण के 72 कार्य शामिल है। मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण और अन्य परियोजना क्षेत्रों का भ्रमण परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है।

मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2006–07 में सात हजार 515 पंचायत प्रतिनिधियों, दस हजार 706 समहित समूहों के सदस्यों को परियोजना प्रबंधन, लेखा संधारण और दो हजार 732 लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। वित्तीय वर्ष 2007–08 में सात हजार 985 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, आठ हजार 15 समहित समूहों के सदस्यों को परियोजना प्रबंधन, लेखा संधारण और दो हजार 770 लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में सफलतम संचालित गतिविधियों के अवलोकन और अनुश्रवण के लिए 183 समहित समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण भ्रमण कराया गया है। ■

***नवा अंजोर परियोजना के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकताओं का स्थानीय स्तर पर पता लगा कर ग्रामीण गरीबों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे है। गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में लाख उत्पादन से रोजगार की काफी संभावनाओं को ध्यान में रखकर सेमीलता, कुसम और पलाश के पौधों का अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जा रहा है।***

## मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर विशेष

# प्रदेश में सुशासन, विकास और कमजोर तबकों की खुशहाली के लिये अमृत-मंथन

nsosUæ tks'kh

समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े अंतिम व्यक्ति के विकास के बगैर देश–प्रदेश की तरक्की को अधूरा ही मानना चाहिये। ज़माने में बदलाव के साथ–साथ परिस्थितियों और जरूरतों में भी परिवर्तन आया है, लेकिन सरकारी तंत्र की जड़ता और अमले की मानसिकता में व्यावहारिकता और संवेदनशीलता की कमी की वजह से आम आदमी की खुशहाल ज़िंदगी का सपना अधूरा ही रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आम लोगों के जीवन में बदलाव की नई संभावनाओं को तलाशने के लिये ही 'मंथन' के जरिये प्रदेश के सुनियोजित विकास की एक नई शुरूआत की है। मुख्यमंत्री ने सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने और तंत्र को जन से जोड़ने के लिये मंथन के जरिये ऐसी अमृत बूंदें तलाशने की कोशिश शुरू की है, जिससे मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में देश के प्रगतिशील राज्यों में सबसे आगे होगा।

प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना को साकार करने में समाज के हर वर्ग, हर तबके को जोड़ने के इरादे से मुख्यमंत्री ने विभिन्न समूहों की पंचायतें आयोजित कर इनमें शामिल लोगों के सुझावों के आधार पर सरकार की रीति–नीति निर्धारित करने की असरदार पहल की है। प्रदेश में नीति निर्धारण और विकास की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा सरकार क `

कार्यकलापों में लोगों की वैचारिक सहभागिता बढ़ाने के इस नवाचार में काफी सफलताएं भी मिली हैं। इसके साथ ही समस्याओं के समाधान तलाशने और व्यवस्थाओं में सुधार के लिये मुख्यमंत्री ने सरकारी तंत्र की मानसिकता में बदलाव लाकर राजधानी भोपाल से गांवों की चौपाल तक काम करने वाले सरकारी अमले को सकारात्मक सोच और कुछ करने की इच्छाशक्ति का प्रेरणादायी मंत्र मंथन के माध्यम से दिया है।

मुख्यमंत्री की पहल पर मंथन की यह प्रक्रिया करीब दो वर्षों के अंतराल से फिर दोहराई गई है, ताकि बदलते परिवेश के अनुरूप सरकारी मशीनरी के सोच और कामकाज के तौर तरीकों में अपेक्षित बदलाव लाकर जनता की भलाई की नई संभावनाओं को आकार दिया जा सके। मंथन–2009 के जरिये मुख्यमंत्री के स्वर्णिम मध्यप्रदेश की रचना के सात इन्द्रधनुषी संकल्पों को साकार करने की सार्थक पहल की गई है। इस मंथन से प्रशासन में जवाबदेही, पारदर्शिता, समयबद्धता और परिणामों की सुनिश्चिता हो सकेगी। मंथन के इस आयोजन का मकसद ही समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के सबसे अधिक जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को

असरदार तरीकों से पहुंचाना है। इसलिये मंथन की यह प्रक्रिया भी लगातार जारी रखी जायेगी। मंथन के परिणाम व्यापक लोकहित की दृष्टि से सार्थक परिवर्तन लायेंगे। सरकारी नियम–कायदों की भूल–भुलैया में उलझे आम लोगों के सुकून के लिये कठिन नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उन्हें परेशानियों से निजात दिलाई जायेगी। नियम–कायदे जनता की जरूरत के अनुसार होना चाहिये यह मंथन का बुनियादी सार है। इसी उद्देश्य से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों के मद्देनज़र प्रभावी योजनाएं कार्यक्रम तय करना मंथन की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जो तय हुआ है, उसे समय सीमा में अपेक्षित गुणवत्ता के साथ पूरा करने का यह संकल्प प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखने का जरिया बनेगा।

मंथन के जरिये शासन प्रशासन को लोकहित में सकारात्मक बदलाव की बहुआयामी चुनौतियों से निपटने की नई दिशा– दृष्टि मिली है। इस आयोजन से प्रदेश की जनता की खुशहाली के परिप्रेक्ष्य में नई संभावनाएं सामने आई हैं। सरकारी तंत्र को अपनी समझ और क्षमता बढ़ाने तथा सक्रियता के साथ जन–आकांक्षाओं को पूरा करने का एक सुलझा हुआ रास्ता मिला है। मुख्यमंत्री ने मंथन के जरिये इस सोच को बदलने की कोशिश करी है कि सिर्फ मुट्ठीभर लोग ही इतने बड़े प्रदेश के विकास की सभी योजनाओं को बनाने और उनकी देखरेख का जिम्मा उठाएं उसके बजाये उनके साथ अब मैदानी अधिकारियों को भी राज्य की तरक्की की दिशा तय करने में अहम भूमिका होना चाहिये। मंथन के जरिये अब 'टीम मध्यप्रदेश बनाने की पहल की गई है। प्रदेश के छोटे–बड़े सभी अधिकारी मिलकर विचार करेंगे, मिलकर सोचेंगे और आम लोगों के हक़ में सभी मिलजुलकर सही फैसले लेंगे तभी प्रदेश की तस्वीर बदलेगी।

'मंथन–2009' के इस अनूठे आयोजन में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्यों तथा मुख्य सचिव, मंत्रालय वल्लभ भवन, राजधानी भोपाल एवं संभाग और जिला कार्यालयों में बैठे छोटे–बड़े सभी ने मिलकर 'मंथन' किया है। प्रदेश के आला अफसर हों या संभाग और जिलों में पदस्थ मैदानी अधिकारी सभी ने एक साथ मिल–बैठकर जनता के दुःख दर्द और विकास की मैदानी हकीक़त को जाना है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने मंथन के जरिये प्रदेश के कायाकल्प के लिये अमृत बूंदें तलाशी हैं। छोटे–बड़े के दर्जे और औपचारिकताओं के दायरे से परे रहकर सभी ने एक साथ बैठकर अपने–अपने अनुभवों और ज्ञान को एक–दूसरे के साथ बांटा है। जिससे सुझाए गए रास्तों पर मजबूत कदम बढ़ाते हुए अब सही मायनों में खुशहाल और स्वर्णिम मध्यप्रदेश की रचना की जा सकेगी। सभी के समान योगदान से अब आने वाले वर्षों में एक ऐसे मध्यप्रदेश का निर्माण हो सकेगा जिस पर आने वाली पीढ़ी को गर्व होगा। ■

# कुपोषण के सामने बेबस दिख रही केन्द्र सरकार

***दक्षिण–पूर्व एशिया में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों में लगभग 74 फीसदी अपने देश के हैं***

दक्षिण–पूर्व एशिया में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे भारत में हैं। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण–पूर्व एशिया के कुल कुपोषित बच्चों (विशेषकर आयोडीन की कमी की वजह से) में से 74 फीसदी भारत के हैं। भोजन में विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की कमी से भारत के बच्चों की ऐसी हालत है। क्या है स्थितिः डॉक्टरों के मुताबिक भारत में कुपोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। खाने की थाली में विटामिन ए, आयरन, आयोडीन एवं फोलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे तेजी से कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। नवजात बच्चे भी कुपोषण के चपेट में आ जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक कुपोषण की वजह से बच्चे न्यूरो, ज्वाइटर, थाइरायड, सांस संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। यूनीसेफ के एक अध्ययन के मुताबिक गर्भवती महिलाओं के कुपोषण की वजह से प्रीनेटल मृत्यु दर एवं बाल मृत्युदर में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकार उदासीनः केन्द्र सरकार ही नहीं बल्कि कई राज्य सरकारें भी कुपोषण से निपटने के लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करने में गंभीरता दिखा नहीं पाई हैं। राजधानी दिल्ली में अति आवश्यक पोषक तत्व विटामिन ए की गोलियों की भारी कमी है। दिल्ली में आयरन की गोलियों एवं आयरनयुक्त भोजन बांटने की योजना फिलहाल अंतिम सांसे गिन रही है। निजी क्लीनिकों द्वारा गर्भवती महिलाओं को आयोडिन की गोलियां बांटने की योजना तो फाइलों में दबी रह गई हैं। ■

# मध्यप्रदेश में औद्योगीकरण की गति तेज

& çrh"k ikBd

मध्यप्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इसके लिये पिछले पांच वर्षों से लगातार कोशिशें की जा रही है। औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। यह इस दिशा में किये गये प्रयासों से स्पष्ट है।

मध्यप्रदेश में पूंजी निवेश के लिये विगत पांच वर्षों से सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट वर्ष 2007 में खजुराहो और इन्दौर, वर्ष 2008 में जबलपुर, सागर और ग्वालियर में सम्पन्न हुई। इसके साथ ही प्रदेश में निवेश हेतु निवेशकों को आमंत्रित करने के लिये मुम्बई और बैंगलोर में रोड शो आयोजित किये गये।

विदेशी पूंजी निवेश के लिये देश के बाहर भी रोड शो हुए। मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विदेशों में निवेशकों और उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में पूंजी निवेश के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इन बहुआयामी प्रयासों के सार्थक परिणाम निकले। पांचों इन्वेस्टर्स मीट के अलावा भोपाल और विदेशों में भी निवेशकों के साथ एमओयू किये गये। वर्तमान में निरस्त होने के बाद जीवित एमओयू की कुल संख्या 307 है। इसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश में कुल 403273.35 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश होगा।

मध्यप्रदेश में पिछले पांच वर्षों में 4791 करोड़ 74 लाख रूपये का पूंजी निवेश हुआ है। कुल 89 बड़े उद्योगों में हुए इस निवेश से लगभग 15 हजार व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिला है। प्रदेश में इस अवधि में 87 हजार से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हुए हैं जिनमें 1099 करोड़ 83 लाख रूपये की पूंजी निवेशित हुई और 2 लाख 12 हजार 113 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ।

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश के लिये उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिये हुई विभिन्न इन्वेस्टर्स मीट को परिणाममूलक निरूपित करते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिये निवेशक उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि मध्यप्रदेश पूंजी निवेश की दृष्टि से विश्व का पहला पसंदीदा राज्य बने। उनकी मंशा के अनुरूप मध्यप्रदेश में ऐसे औद्योगिक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है ताकि भारत में निवेश के लिये आने वाले विश्व के किसी भी देश के निवेशक की मध्यप्रदेश पहली पसंद बन सके।

इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन के फलस्वरूप 2008–09 में इंडस्ट्रियल इन्टरप्रेनियर्स मेमोरेण्डम दाखिले में प्रस्तावित निवेश दृष्टि से मध्यप्रदेश 11वें स्थान से बढ़कर 8वें स्थान पर आ गया है। इसी तरह इसी मेमोरेण्डम के अंतर्गत स्थापित उद्योगों की दृष्टि से मध्यप्रदेश 9वें और निवेश की दृष्टि से 10वें स्थान पर आंका गया है।

राज्य सरकार ने फरवरी – 2010 में इन्दौर में डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2 आयोजित करने का निर्णय लिया है। समिट का फोकस एग्री, एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग पर होगा।

डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश : इन्वेस्टमेंट ड्राइव– 2009–10 के अन्तर्गत पहला कार्यक्रम 27 अगस्त को मुम्बई में संपन्न हुआ। इसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के देशभर के लगभग 200 प्रमुख निवेशकों की हिस्सेदारी रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये जिलों के वर्गीकरण की व्यवस्था समाप्त की जाएगी और प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के उद्योगों को आवश्यक छूट और सुविधाएं प्राप्त होंगी।

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में मध्यप्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश की बेहतर संभावनाओं, उपलब्ध संसाधनों और अवसरों को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये हरसंभव सहायता, सुविधा और छूट प्रदान करने के लिये कृतसंकल्प है। राज्य सरकार की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी नीति में इन पर आधारित उद्योग स्थापित

करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

मध्यप्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिये देश भर के निवेशकों को आमंत्रित करने के लिये मुम्बई की तर्ज पर हैदराबाद, बैंगलोर और चण्डीगढ़ में भी रोड शो का आयोजन किया जायेगा। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विदेशी निवेशकों से सम्पर्क कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिये प्रेरित किया जा रहा है। इनमें साउथ कोरिया (सिओल), ताईवान, नीदरलैण्ड और इजराइल के निवेशक शामिल हैं।

डिफेंस उत्पादों का निजी क्षेत्र में उत्पादन करने के लिये भी इन निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। इसके अंतर्गत शाजापुर–देवास इन्वेस्टमेंट्स मोडस में राजगढ़ जिले में पॉवर इक्यूपमेंट मैन्यूफ्रैक्चरिंग हब और डिफेंस इक्यूपमेन्ट एसईजेड का चयन 'अरली बर्ड' प्रोजेक्ट के रूप में करने के लिये ब्यावरा (राजगढ़) के समीप भूमि का चयन किया जा चुका है।

मध्यप्रदेश सरकार राज्य में व्यापार और उद्योग का विकास, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रदेश को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने और राज्य की विकास दर अन्य विकसित राज्यों के समतुल्य करने के उद्देश्य से वर्ष 2004 में उद्योग नीति और कार्ययोजना घोषित की गई थी। यह नीति पिछले पांच वर्षो से प्रदेश में लागू है। इसके तहत प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण करने में राज्य सरकार को भारी सफलता मिली है।

उद्योग नीति के अन्तर्गत शासकीय नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने और प्रशासन को उद्योग मित्र (इंडस्ट्री फ्रेडली) बनाने से प्रदेश में औद्योगीकरण की गति में तेजी आई है। यही नहीं बल्कि विश्व स्तर की अधोसंरचना विकसित कर, प्रवासी भारतीयों को पूंजी निवेश के लिये आकर्षित किया गया है। इसके साथ–साथ प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश के लिये भी पुरजोर कोशिशें जारी हैं।

प्रदेश के संसाधनों का बेहतर उपयोग और उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही प्रदेश के लघु उद्योगों के पुनर्जीवन के लिये उद्योग मित्र योजना शुरू की गई जो वर्ष 2004 से अब तक प्रभावशील है और इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

मध्यप्रदेश में प्रभावी और गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना और उसके संचालन को सरल और सुचारू बनाने की दृष्टि से सिंगल एजेंसी क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया गया है। मध्यप्रदेश इस नयी व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।

उद्योगों की विभिन्न शासकीय विभागों से अनुमति अथवा सम्मति लेने में होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए सिंगल एजेंसी क्लीयरेंस सिस्टम शुरू किया गया। इसके तहत औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से संबंधित अधिकार आठ शासकीय विभागों से लेकर उद्योग विभाग को दिये गये हैं।

इसी प्रकार स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन एक छत के नीचे करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़े। इससे हितग्राहियों को एक छत के नीचे योजनाओं संबंधी सभी जानकारी मिलना सुनिश्चित हुआ।

राज्य सरकार की नयी उद्योग नीति शीघ्र घोषित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इस घोषणा के साथ मौजूदा उद्योग नीति एवं कार्य योजना को नयी नीति बनने तक निरंतर रखने के निर्देश दिये हैं।

मौजूदा उद्योग नीति को पुनरीक्षित करने के साथ ही नयी नीति बनाकर उसके प्रावधानों से संबंधित नियम, प्रक्रिया और अधिसूचनाओं का प्रकाशन भी यथाशीघ्र किया जायेगा।

मध्यप्रदेश में इस वर्ष 13 हजार करोड़ रूपये की लागत की परियोजनाओं की स्थापना संभावित है। इन परियोजनाओं में 10 हजार 300 करोड़ रूपये की भारत–ओमान रिफायनरी लिमिटेड के अलावा अभिषेक इंडस्ट्रीज–बुधनी, ल्यूगांग इंडिया लिमिटेड–पीथमपुर, रीजेन्ट ड्रग–मालनपुर, अल्फा लेबोरेटरी, एसईजेड–इन्दौर, सिपला एसईजेड–इंदौर, सोनिक बायोकेम एसईजेड–इंदौर और जय कार्प–इंदौर शामिल हैं।

दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत पीथमपुर–धार–मांडू इन्वेस्टमेंट रीजन में त्वरित अमल वाली चार अरली बर्ड परियोजनाओं का चयन कर एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। इन परियोजनाओं में इंदौर हवाई अड्डे से पीथमपुर तक की सड़क के दोनों ओर इकानॉमिक कॉरिडोर के विकास, उज्जैन में नॉलेज सिटी, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में जलप्रदाय में सुधार एवं दूषित जल के प्रबंधन और पीथमपुर इन्टीग्रेटेड मल्टी मोडल लाजिस्टिक हब के विकास की परियोजना शामिल हैं।

राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 में प्रदेश के रेडीमेड गारमेंट उद्योगों को कुशल प्रशिक्षित कारीगर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भोपाल में गोविंदपुरा और रायसेन में मंडीदीप में एपेरल ट्रेनिंग एंड सेटेलाइट डिजाईन सेंटर की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया है।

केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में स्वी.त एसईजेड की 45 योजनाओं में से 16 पूर्ण हो चुकी हैं। इसी तरह केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत इंदौर के एपेरल पार्क, पीथमपुर के ऑटो क्लस्टर, पांढुर्ना के इंडस्ट्रियल क्लस्टर और ग्वालियर के स्टोन पार्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ■

# केंद्रीय रवैया पक्षपातपूर्ण : सुशील मोदी

*गंगा मैली हो चुकी है। लेकिन सफाई के नाम पर केंद्र और बिहार सरकार के बीच आपसी सहमति नहीं बनने से विभिन्न कार्ययोजनाएं अधर में लटकी नजर आ रही हैं। इस मसले पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से दैनिक समाचार पत्र की संवाददाता से हुई बातचीत के अंश।*

**राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों पर राज्य सरकार कितनी गंभीर है?**

निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को लेकर बेहद गंभीर हैं। बेगूसरायए बक्सर और भागलपुर के लिए नालियों और जल निकासी (सीवेज) की स्कीम को लगभग मंजूरी मिल चुकी है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) हम प्राधिकरण को भेज रहे हैं।

ये तीन शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। पटना शहर के घाट की सीवेज स्कीम लगभग अंतिम चरण में है। हम गंगा नदी को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।

**गंगा से जुड़ी परियोजना को लेकर कितनी चुनौतियां हैं?**

इससे पहले राजीव गांधी में शासन काल में जो गंगा एक्शन प्लान बना था वह पूरी तरह से असफल रहा। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद गंगा का पानी प्रदूषित ही रहा। अब भी इस परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर काफी चुनौतियां हैं।

केंद्र सरकार को पहले गंगा एक्शन प्लान की खामियों की समीक्षा करके समुचित कदम उठाने चाहिए ताकि पैसे की बरबादी न हो और गंगा नदी के अस्तित्व को सुरक्षित बनाए रखा जा सके।

**बिहार में निकासी की परियोजनाओं के लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं? इस परियोजना में कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?**

नालियों और जल की निकासी के लिए हम सलाहकारों की सहायता ले रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में काम करने वाले सलाहकार सीवेज योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रहे हैं। अभी खर्च के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी तो परियोजना की प्रक्रिया पर ही काम हो रहा है और रिपोर्ट तैयार हो रही है।

**केंद्र सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप?**

केंद्र सरकार बिहार को लेकर काफी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। हाल ही में भागलपुर के पीरपैंती पावर प्लांट के लिए गंगा के पानी का इस्तेमाल न करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए स्थानीय स्तर पर जलाशय बनाने की बात कही है। अगर केंद्र सरकार का यही रवैया रहा तो बिहार के पावर प्लांट के विकास की परियोजना अधर में रह जाएगी।

ऐसे में नबीनगर में एनटीपीसी और रेलवे की साझीदारी से बन रहे पावर प्लांट को भी बनने की मंजूरी नहीं देने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। इससे पहले पानी के बंटवारे को लेकर भारत–बांग्लादेश संधि के वक्त भी बिहार से कोई सलाह नहीं ली गई। अब इस वक्त हालात यह हैं कि जिस वक्त पानी की कमी होती है उस वक्त भी हमें बांग्लादेश को पानी देना होता है।

बिहार में गंगा का पानी बक्सर में प्रवेश करता है उसके बाद नेपाल और उत्तरी बिहार से आने वाली नदियों का पानी इसमें मिलता है। इससे बिहार में काफी तबाही भी मचती है जिसका खामियाजा इस राज्य के लोगों को भुगतना पड़ता है, लेकिन अब केंद्र सरकार यह कहती है कि हम इस पानी का इस्तेमाल विकास के लिए नहीं कर सकते तो यह बिल्कुल गलत है। ■

➡ *पृष्ठ 14 का शेष*

जाता है। मानव संसाधन मंत्रालय का कार्यक्षेत्र अब और विस्तृत हो गया है, क्योंकि उसे भविष्य में किस प्रकार के कितने सक्षम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी इसका अनुमान लगाना होगा और उनके प्रशिक्षण आदि की सुविधा का प्रावधान ताकि लोग बेकार न रहें और किसी क्षेत्र में कम भी न पड़ें। निजी संस्थानों में जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें यदि सरकार उचित नौकरी नहीं दे सकती और उनका सदुपयोग नहीं कर सकती तो बेकारी के विकराल रूप को इन लोगों को बेकार करके बढ़ाना देशहित में नहीं होगा। इस तरह तो शिक्षा सुधार मजाक ही साबित होंगे। बार–बार शिक्षा के ढाँचे को बदलते रहने के बजाय एक सुनिश्चित और व्यवस्थित शिक्षा क्रम अपनाना चाहिए ताकि प्रतिभाएँ और ज्यादा निखर कर सामने आएँ। ■

# दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग

fnल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से 10 अक्टूबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर त्यागपत्र की मांग की। उन्होंने कहा कि माननीय लोकायुक्त ने यह सम्प्रेक्षण किया है कि 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विज्ञापन अभियान हेतु सरकारी और जन–धन के दुरूपयोग के आरोप को देखते हुए ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि दिल्ली लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1995 की धारा 2 (ख) के साथ पठित धारा 7 के अधीन एक जांच प्रारम्भ करने के लिए आधार हैं। उन्होंने यह सूचना दी थी कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री बिजेन्द्र गुप्ता ने 17 अगस्त, 2009 को सरकारी और जन–धन के विज्ञापन अभियान में दुरूपयोग के विरूद्ध एक शिकायत फाइल की थी।

माननीय लोकायुक्त ने कल एक नोटिस जारी करके 27 अक्टूबर, 2009 तक जवाब मांगा है। उन्होंने शीघ्र न्याय के हित में इस मामले में एक वादमित्र भी नियुक्त किया। उन्होंने लोकायुक्त की सहायता के लिए श्री सौरभ कृपाल को वादमित्र नियुक्त किया है।

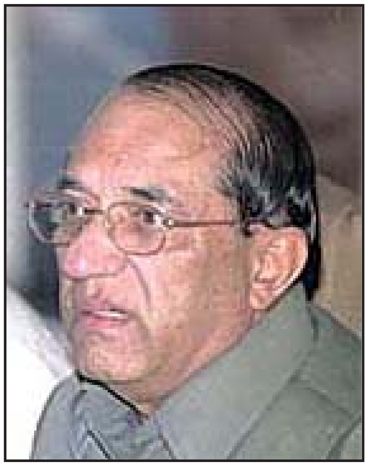

अपनी शिकायत में श्री गुप्ता ने यह सूचित किया कि वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री ही सूचना और प्रचार विभाग की प्रभारी थी और उन्होंने एक विस्तृत प्रचार अभियान की नीति तैयार की और नवम्बर 2008 में होने वाले चुनाव को जीतने के लिए सरकार की सहायता के लिए सूचना और प्रचार निदेशक के माध्यम से उसको क्रियान्वित किया। शिकायतकर्ता ने तत्कालीन दिल्ली के सूचना और प्रचार के निदेशक श्री उदय सहाय द्वारा लिखित एक लेख के आधार पर जो हिन्दी दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित किया गया था, संलग्न किया है जो शिकायत के एनैक्सचर (1) पर है जिसकी अंग्रेजी में अनुदित प्रति एनैक्सचर बी पर रखी है। उस लेख का शीर्षक था 'शीला की कैम्पेन रणनीति'।

माननीय लोकायुक्त ने इस बात का संज्ञान किया है कि मुख्यमंत्री और यूपीए की अध्यक्षा के चित्र वाले बड़े–बड़े होर्डिंग्स मैट्रो स्टेशनों, बस शैल्टरों पर लगाए गए, रेडियो जिंगल और टीवी स्पाट के रूप में प्रसारित भी किए गए। प्रचार अभियान नीति का केन्द्र बिन्दु कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया विज्ञापन था जो सम्पूर्ण अभियान नीति का एक अभिन्न अंग था। यह भी तर्क दिया गया है कि चुनाव के बाद इस प्रकार के कोई भी विज्ञापन उनकी पार्टी द्वारा नहीं दिए गए जो स्पष्टतया यह दर्शाता है कि यह चुनाव नीति का ही भाग था जिसके फलस्वरूप इन विज्ञापनों पर 22. 5 करोड़ रूपए खर्च किए गए।

उन्होंने यह भी दलील दी कि मुख्यमंत्री के रूप में वह सरकारी निधि के एक न्यासी के रूप में कार्य कर रही थीं और उनका उपरोक्त व्यवहार उनसे अपेक्षित ईमानदारी और सद्व्यवहार के अनुसार नहीं था क्योंकि सम्पूर्ण निर्वाचन अभियान इस उद्देश्य और जानकारी के साथ क्रियान्वित किया गया कि इस जन–धन का उपयोग उनकी राजनीतिक पार्टी के निजी लाभ के लिए होगा।

माननीय लोकायुक्त ने इस आरोप पर भी ध्यान दिया है कि चुनाव अभियान की योजना और उसका क्रियान्यन सरकारी धन का दुरूपयोग करके किया गया है। विज्ञापनों की बड़ी संख्या और उनपर लिखे गए वाक्य तथा जनप्रतिनिधियों के चित्र यह दर्शाते हैं कि राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया जैसा कि ऊपर लिखित लेख में भी प्रकट किया गया है। ■

- *सन 2008 विधानसभा चुनावों के दौरान विज्ञापन अभियान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी और जन–धन का दुरूपयोग करने के विरूद्ध लोकायुक्त को प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले।*
- *दिल्ली में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री से उनके द्वारा राजनीतिक प्रयोजन के लिए जन–धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलने पर उनसे त्यागपत्र की मांग की*

# काशी में महारानी लक्ष्मीबाई का भव्य स्मारक बनाने का संकल्प लें : डॉ. मुरली मनोहर जोशी

महारानी लक्ष्मीबाई न्यास, राष्ट् सेविका समिति एंव भारत विकास परिषद की ओर से 16 अगस्त को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अस्सी स्थित गोयनका का संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उनके अदम्य साहस ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिये थे। ऐसी भारतीय नारी के आदर्शों और विचारों से हम सबकों प्रेरणा लेनी चाहिए।

समारोह के मुख्य अतिथि सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा काशी में काशी की बेटी मनु और झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का भव्य स्मारक अवश्य बनेगा। यह पवित्र कार्य काशी के लोगों को आगे आकर पूरा करना होगा। केवल सरकार के आसरे कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर जोशी ने कहा कुछ लिखित इतिहास पूरी तरह झूठा एवं विकृत है। हमारी वैदिक सभ्यता, ज्ञान–विज्ञान एवं गौरवशाली इतिहास, मुगलों और अंग्रेजों ने अपनी प्रगति के चक्कर में विकृत कर डाला है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारे गौरवशाली संघर्ष का अप्रतिम साक्षी है। उसे विकृत इतिहासकारों ने 'गदर' कहने की कुचेष्टा की है। इतिहास में हमें अज्ञानी, कायर, पराजित आदि संज्ञाओं से सम्बोधित किया, लेकिन हमारा इतिहास संघर्ष और अपराजेय कर्तव्य का बोध कराता है। हमारे वीरों ने कभी पराधीनता के आगे हार नहीं मानी। 22 वर्ष 7 माह की महारानी लक्ष्मीबाई इतिहास का वह पृष्ठ बनी जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलता। डॉ. जोशी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं, न्यास के पदाधिकारियों, पत्रकारों, प्रबुद्धजनों एवं सर्व सामान्य से लक्ष्मीबाई के भव्य स्मारक के निर्माण हेतु चार कदम आगे बढ़ने के साथ अपना भी सब प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष और जीवन के सन्दर्भ में स्थानीय एवं व्यापक स्तर पर निबन्ध प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए आयोजन पर दस हजार रुपये तक पुरस्कार देने की घोषणा की, साथ ही पूर्वांचल के लोगों का स्वातन्त्र्य आन्दोलन में योगदान विषय पर शोध कराने के लिए आर्थिक सहयोग का भी आश्वासन दिया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रो. उषा किरन ने इस पवित्र अवसर पर सभी को बधाई देते हुए महारानी के जीवन चरित्र पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी बेटियों ने वीरांगना लक्ष्मीबाई का अनुसरण करें। सच्चाई और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना सीखें। हार न मानकर विजय की ओर अग्रसर हों। साथ ही यह ध्यान रखें विधवा, हारी हुई महिला नहीं होती, उसे वीरांगना लक्ष्मीबाई बन कर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ने का काम करना होता है। देश की बेटियाँ, गुणवान, बलवान संस्कारवान, चरित्रवान और संघर्षशील बनें।

कार्यक्रम का शुभारम्भ महापौर कौशलेन्द्र सिंह ने महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण से किया। निवेदिता कन्या इण्टर कालेज की बालिकाओं ने वन्देमातरम् राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रमों की श्रृंखला का शंखनाद किया। कार्यक्रम में धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, हरिश्चन्द्र बालिका इण्टर कालेज, संजय शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, मोहिनी देवी रूगंटा शिशु मंदिर, दुर्गाचरण कन्या इण्टर कॉलेज, विवेकानन्द विद्याभारती, वनवासी छात्रावास–पिशाचमोचन, लक्षना देवी शिशु मंदिर, संत अंतुलानन्द कान्वेन्ट स्कूल, गोपी राधा कृष्ण कॉलेज, भारतीय विद्या सरस्वती शिशु मंदिर–टिकरी सहित दर्जनों अन्य विद्यालयों की छात्राओं ने शारीरिक, योग, अग्निशमन, डम्बल, योगासन, खड्ग तथा अत्यन्त मनमोहक घोषवादन तथा नाटिका का प्रदर्शन किया तथा महापौर ने विद्यालयों को स्मृति चिह्न एवं पुरस्कार प्रदान किया।

महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक न्यास के मंत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय ने न्यास के कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया तथा श्रीमती नमिता अग्रवाल, रिंकी अग्रवाल, रीता केशरी, प्रीति पाण्डेय तथा सुमन तिवारी आदि ने विभिन्न कार्यक्रमों का अलग–अलग संचालन किया। हजारों छात्र–छात्राओं ने घोष के साथ लक्ष्मीबाई जन्म स्थली आराजी सं. 3110 की चतुर्दिक परिक्रमा घुड़सवार लक्ष्मीबाई के पीछे चल कर किया। घोड़े पर वीरांगना लक्ष्मीबाई के वेश में धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय के छात्रा कुमारी स्वाती राय के नेतृत्व में हजारों छात्र–छात्राओं एवं नर–नारियों ने घोष की धुन पर पथ संचलन करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली आराजी सं. 3110 मौजा भैदनी की चतुर्दिक परिक्रमा करते हुए एक अन्य स्थान आराजी सं. 3111 पर अपने श्रद्धा सुमन प्रतीकात्मक रूप से लक्ष्मीबाई को अर्पित किये। ■

# भारत को चाहिए आव्रजन-भय से मुक्ति

&,u- d- flg

e हाराष्ट्र के चुनाव हो चुके हैं। उम्मीद की जाती है कि उत्तर भारतीयों के पलायन के खिलाफ कुछ पार्टियों की भीड़खींचू नारेबाजी अब भुला दी जाएगी। इधर जब महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां अनावश्यक क्षेत्रीय कट्टरता में उलझी थीं, उस समय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विकास रपट–2009 जारी हुई, जिसका शीर्षक था– अवरोधों के पार : मानवीय गतिशीलता और विकास। मानवाधिकार विकास रपट मूलतः एक ऐसी सालाना रपट है, जो सुपरिभाषित मानदंडों के आधार पर देशों को उनकी उपलब्धियों के मुताबिक उनका क्रम तय करता है। 2009 की ताजा रपट के अनुसार यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर 182 देशों में भारत की स्थिति 134 वें नंबर पर है। अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में भारत की स्थिति में पिछले कुछ सालों में गिरावट आई है। सन् 2007 में भारत 126 वें नंबर और सन् 2008 में 134 नंबर पर था। वैसे कुल मिला कर भारत ने निःसंदेह लगातार प्रगति की है। इस दौरान इसकी मूल्यांकन सूचकांक (वैल्यू) 0.556 से बढ़ कर 0.612 तक पहुंच गया।

इस साल यूएनडीपी की रपट ने मनुष्य की ज्यादा गतिशीलता के लिए पूरी दुनिया में उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर फोकस किया है। क्योंकि मानव विकास की उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक है। पलायन पर होने वाली बहसें आमतौर पर विकासशील देशों से विकसित देशों की यात्रा पर केंद्रित रहती हैं। फिर भी आंकड़ें बताते हैं कि लोगों की बहुत बड़ी आबादी अपने ही देश में पलायन करती है। रपट का अनुमान है कि आंतरिक आव्रजनों की संख्या 74 करोड़ हैए जो कि एक देश से दूसरे देश में जाने वालों की संख्या का चार गुना है। जबकि दुनिया में 20 करोड़ आव्रजन एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हैं। यहां विशेषज्ञों का मूल निष्कर्ष यह है कि कई वजहों से विकास को गति देने में पलायन की सकारात्मक भूमिका रहती है।

सबसे पहले तो इससे श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ती है और मजदूरी की प्रतिस्पर्धा होने से सकल उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। कई तरह की आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं, जो अप्रवासी मजदूरों के अभाव में प्रतिस्पर्धा खो सकती थीं। आमतौर पर अप्रवासी छोटी नौकरी करें या बड़ी, वे उस देश को अर्थवान और समृद्ध बनाते हैं जहां वे काम करते हैं। इस प्रकार पलायन और विकास में एक तरह का सकारात्मक रिश्ता है।

दूसरी बात यह है कि बाहरी आमदनी चाहे देश के बाहर हो या भीतर, उससे आव्रजनों के मूल स्थान में जीवन का स्तर सुधरता है। इससे विकास का ज्यादा समतावादी वितरण होता है और कई मामलों में इससे शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा लोगों की पहुंच बनती है। ज्यादातर विकासशील देशों में बाहरी आमदनी विदेशी अनुदान के मुकाबले आय का ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत होती है।

तीसरी बात यह है कि जो देश बहु सांस्कृतिक और जातीय विविधता की नीति को बढ़ावा देते हैं, वे इससे तमाम फायदे उठा सकते हैं। अखंडता को बहुसंस्कृतिवाद से जोड़ देने पर स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के तालमेल को बिगाड़े बिना उस देश में एक तरह का सांस्कृतिक निषेचन और कायाकल्प होता है।

चौथी बात यह है कि जो आव्रजन अस्थायी होते हैं वे अपने मूल स्थान पर लौटने पर नए विचार, ज्ञान और नए किस्म की प्रौद्योगिकी लेकर आते हैं। इससे समाज का सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए कभी– कभी उच्च कुशलता वाले लोग जैसे डॉक्टर, नर्स, शिक्षक और इंजीनियरों का विकसित देशों में पलायन विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय हो जाते हैं। यूएनडीपी की रपट में मानवीय गतिशीलता को बनाए रखने के लिए छह सूत्री सुधार बताए गए हैं।

पहला ज्यादा मानवीय प्रवाह बनाने के लिए कम कुशलता वाले लोगों के प्रवेश पर लगी रोक को हटाना। दूसरा सुझाव आव्रजनों की स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच बना कर उनके बुनियादी मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा सुझाव पलायन का खर्च कम करने के बारे में है। इसके लिए एक तरफ शोषक संस्थाओं को नियंत्रित करना और साथ ही इस बात की व्यवस्था करना कि आव्रजन अपनी कमाई कम खर्च पर मूल स्थान को भेज सके। चौथा सुझाव आव्रजन और स्थानीय समुदायों के बीच विवादों के समाधान की समुचित व्यवस्था करने के लिए है। पांचवा सुझाव मूल देश संक्रमण वाले देश और गंतव्य वाले देशों में आव्रजन को एक विकास की रणनीति का मूल तत्व बनाए जाने के बारे में है। छठा सुझाव मंदी के प्रभाव के कारण पैदा हुए उल्टे आव्रजन की स्थितियों से निपटने के बारे में है। निर्यात और रोजगार केंद्रित तमाम उद्योगों में नौकरी के अवसर घट गए ज्यादातर स्थानों में आव्रजन छोटी नौकरियों पर निर्भर हो गए। नए आव्रजन की स्थितियां कम हो गईं। कई मामलों में लोग अपने गांव और घर लौट गए।

संक्षेप में कहें तो दुनिया लगातार सीमाविहीन हो रही है। इससे पता चलता है कि सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए आव्रजन को योजनाबद्ध तरीके से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जिन कारणों से आव्रजन होता है, वे अपने में बहुत मजेदार हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह घरेलू स्तर पर नौकरी और प्रशासन की खराब स्थितियां होती हैं और वह गंतव्य देश में एक बेहतर जीवन स्तर और रोजगार का अच्छा अवसर पाने के प्रयास में जाता है। बेहतर जीवन की लालसा आव्रजन को बहुत कठिन संक्रमण से गुजरने को बाध्य करती है। आप इसे पसंद करें या न करें पर पारस्परिक तौर पर निर्भर विश्व में बढ़ता आव्रजन एक ऐतिहासिक आवश्यकता है।

दुनिया का जोर मानवीय गतिशीलता बढ़ाने पर है। यह विडंबना है कि देश के कुछ हिस्से में कुछ संकीर्ण नजरिए की पार्टियां आंतरिक आव्रजन पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं। यह समझदार अर्थशास्त्र और ऐतिहासिक अनुभव के तर्क के विपरीत है। दुनिया का

शेष अगले पृष्ठ पर ➡

# चीन को उसी के खेल में मात देने की जरूरत

&i"ijtu

VSa शन लेने का नहीं देने का है। कभी–कभार ऐसे चालू फिल्मी डॉयलॉग की जरूरत गंभीर कूटनीतिक मामलों में भी पड़ जाती है। जी हां, बात चीन के संदर्भ में हो रही है, जो कल तक अरुणाचल के मामले में भारत को आंखें दिखा रहा था और अब कश्मीर के मामले में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

कश्मीर पर बयानबाजी करते वक्त चीन भूल जाता है कि उसके यहां भी एक कश्मीर पल रहा है। इसके लिए उइगुर लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी 21 अक्टूबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ग्वांतेनेमो से लाए गए उइगुर कैदियों को लेकर सुनवाई हुई। ये 13 उइगुर चीन को सौंपे जाने से बचने के लिएए अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। तय यह हुआ है कि 2010 के शुरू में नौ जजों की पीठ इस पर फैसला देगी। अक्टूबर, 2001 में अमेरिकी फौजियों ने 22 उइगुर युवकों को अफगानिस्तान के एक कैंप से उठा लिया था और उन्हें क्यूबा के कुख्यात ग्वांतेनेमो बे डिटेंशन कैंप में 775 कैदियों के साथ रखा था। ग्वांतेनेमो के बाकी बचे 247 कैदियों की रिहाई के लिए सुनवाई होनी है, उनमें से 13 उइगुर हैं।

चीन 2001 से ही अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है कि उइगुर कैदी उसे सौंप दिए जाएं। तब से अब तक जो नौ उइगुर कैदी अमेरिका ने छोड़े, उनमें से पांच अल्बानिया में और बाकी चार बरमूडा में बसा दिए गए। चीनी स्वायत्त प्रदेश शिन्चियांग को पूर्वी तुर्किस्तान, उइगुरिस्तान नामों से भी जाना जाता है। यहां 80 लाख उइगुर, 10 लाख कजाख और 16 लाख दूसरे समुदायों के लोग थांग, छिंग वंशों के शासन के समय से ही रह रहे थे। 1 अक्टूबर 1955 को शिन्चियांग पर चीन का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया पर इससे पहले बहुत सारे चीनी 1943 से जारी युद्ध में मारे गए। उनमें से माओत्से तुंग का भाई जेमिन भी था।? चीनी कब्जे के बाद कोई नौ लाख हान चीनी शिन्चियांग में बसाए गए। लोप नोर परमाणु केंद्र के कारण शिन्चियांग सामरिक रूप से चीन के लिए महत्वपूर्ण सूबा है। लोप नोर वही जगह है, जहां 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने पहला परमाणु परीक्षण किया था।

सबके बावजूद शिन्चियांग की राजधानी उरुम्छी में 5 जुलाई को हुए दंगे से दुनिया भर में यह संदेश तो गया कि उइगुर आजादी के अलावा कुछ नहीं चाहते। चीन ने कोई आधा दर्जन उइगुर युवकों को दंगे के आरोप में 10 अक्टूबर को फांसी दे दी। इस फांसी और दंगे के दौरान उइगुर मुसलमानों पर सितम ढाए जाने का तुर्की ने जमकर विरोध किया। पूर्वी तुर्किस्तान या उइगुरिस्तान का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यहां जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है। शुरू में काराकोरम का सिल्क रूट खुलने से चीन गदगद था कि पाकिस्तान से उसका सीधा संपर्क हो गया। लेकिन सिल्क रूट अब उसके लिए सिरदर्द बन चुका है क्योंकि हज के बहाने हजारों उइगुर रेशम मार्ग से पाकिस्तान जाते हैं और जब लौटते हैं तो उनके साथ जिहाद का फतवा होता है। दिखावे के लिए पाकिस्तान हर साल कुछेक दर्जन उइगुर आतंकवादियों को चीन को सौंपता है। उइगुर आतंकी तैयार करने वाला पाकिस्तान फिर भी चीन को प्यारा है।

सवाल यह है कि भारत का सरोकार उइगुर मुसलमानों पर हो रहे सितम और उइगुरिस्तान की आजादी से क्यों नहीं होना चाहिए? इसी तरह का सवाल ताइवान के संदर्भ में भी है। भारत के लिए अब भी ताइवान से कूटनीतिक रिश्ते कायम करने की दुविधा है जबकि पश्चिम अफ्रीका का छोटा सा देश बुरकिनाफासो ने ताइवान से कूटनीतिक संबंध जोड़ रखा है। अकेले बुरकिनाफासो ही नहीं, दुनिया के कोई दर्जन देशों के ताइवान से कूटनीतिक रिश्ते हैं। ये रिश्ते इस बात की गवाही देते हैं कि में ताइवान का हक मारकर चीन जोर–जबरदस्ती से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना। जून, 2007 में कोस्टारिका ने जब तक ताइवान को छोड़ चीन को मान्यता नहीं दी, तब तक ताइपे के पाले में 25 देश थे। ऐसा लगता है कि भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देने की जल्दी कर दी। अगर अरुणाचल और कश्मीर चीन के लिए विवादित क्षेत्र है तो ताइवान से लेकर तिब्बत तक चीन अखंड क्यों है? क्यों भारत वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देना जारी रखे? दलाई लामा ताइवान भूकंप पीड़ितों को देखने गए तो चीन को टेंशन हो गया। इस तरह का टेंशन देते रहना चाहिए। नई दिल्ली के वसंत विहार में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है। क्या यहां कूटनीति से जुड़ा कोई काम नहीं होता? होता है पर छिप–छिपाके। तो क्या अब भी चीन से लाज–लिहाज की जरूरत है? ■

---

➡

कृत्रिम विभाजन विनाशकारी साबित होगा। यह भारत जैसे विशाल देश में तो और घातक साबित होगा क्योंकि पूंजी, प्रौद्योगिकी, कौशल और इंसान की निर्बाध गतिशीलता की जरूरत है। उम्मीद की जाती है कि महाराष्ट्र में हाल में चली नारेबाजी अब भुला दी जाएगी और आंतरिक आव्रजन की सकारात्मक भूमिका को ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकेगा। हालांकि यूएनडीपी की रपट भारत के आंतरिक आव्रजन के बारे में बहुत कम चर्चा करती है लेकिन अब समय आ गया है कि भारत में आंतरिक आव्रजन के फायदों के बारे में एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन कराया जाए। एक भारतीय शोध संस्थान की तरफ से होने वाला तटस्थ अध्ययन शंकाओं को भगाएगा और मिथकों को ध्वस्त करेगा। यह आव्रजन को वह वाजिब जगह दिलाएगा जो विकास की रणनीति में उसके लिए होनी चाहिए। ■